प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ...सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

आपको गतिविधि के समय स्थिर और विश्राम के समय क्रियाशील रहना सीख लेना चाहिए।
इंदिरा गांधी

वर्ष-08, अंक - 38 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 09 जुलाई 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

यह कैसा रख रखाव: जनता के पैसों की बर्बादी

क्या यही पहचान है स्वच्छ शहर इंदौर की

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

इंदोर। एक और जहां प्रदेश के कद्दावर नेता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर को उसका वाजिब हक दिलाने और इंदौर की अनदेखी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। वहीं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आए दिन ऐसी खबरें आ रही है जो स्वच्छता के दामन पर दाग लगा रही है। इंदौर में पिछले दिनों दूषित पेयजल से कई लोग असमय काल कलवित हो चुके हैं इस घटना ने इंदौर की छवि को देश में बदनाम किया था। वहीं पिछले दिनों अस्पताल में नवजात शिशुओं को चूहो द्वारा कुतरने का भी मामला सामने आया था। हाल ही लगभग 300 करोड रुपए की लागत से बने बीआरटीएस यानी बस रेपीट ट्रांसीट सिस्टम जो शहर के बीचो-बीच बना लगभग 12 किलोमीटर लंबा कारीडोर हटाया भी गया है। यानि पहले बनाने में खर्च और उसके बाद हटाने में खर्च। सरकारी धन के दुरुपयोग के ऐसे कई मामले इंदौर की छवि को धूमिल कर रहे हैं। हाल ही में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें अस्पतालों में बंद पड़ी मशीनों पर भी मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर इंदौर का नाम शर्मसार हुआ है। आम शहरवासी अपने आप को इंदौरी कहलाने में गर्व महसूस करता है लेकिन इस प्रकार की घटनाएं इंदौर की छवि धूमिल करती है। और आम जनता के गाढ़े पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाती है उस धन का इस प्रकार दुरुपयोग होना निश्चित रूप से आम जनता की अपेक्षाओं पर कुठारघात करना है। जनता टैक्स सरकार को विकास कार्यों के लिए देती है न कि इस प्रकार के दुरुपयोग के लिए। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पतालों का मामला सामने आया है। जनता के पैसे

पिछले 49 माह यानी 4 साल से अधिक समय से बंद पड़ी एक करोड़ 44 लाख रुपए की कीमत की 57 मशीनों के रखरखाव के नाम लगभग 42 लाख रुपए खर्च कर दिए। आश्चर्य की बात है कि, इनमें से कई मशीन कबाड़ हो चुकी है। जंग लगी इन मशीनों के कुछ मॉडल भी सरकार ने बंद कर दिए हैं। बावजूद इसके इन्हें कागजों में चालू दिखाकर मेंटेनेंस के नाम पर खेला किया जाता रहा है। इसके अलावा एक और आश्चर्यजनक बात यह सामने आई कि, एक मशीन का दो एजेंसी द्वारा मेंटेनेंस किया जाना बताया गया और दोनों ही कंपनियां बिना कुछ करें धरे कबाड़ मशीनों का मेंटेनेंस कर भुगतान लेती रही।

मामला सामने आने के बाद प्रशासन सख्त हरकत में आया और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पांच अधीक्षकों को नोटिस और चार कर्मी को हटाने के आदेश दिए हैं। वही संबंधित कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड करने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि, ये सब कार्रवाई मामला मीडिया द्वारा उठाए जाने के बाद ही क्यों...?

क्या विभाग की अपनी कोई आंतरिक व्यवस्था नहीं है जिससे कि इस प्रकार की लापरवाही होने ही न पाए। अक्सर घटना के घटित होने के बाद भी लीपापोती और जांच के नाम पर केवल नोटिस देकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। मामला सार्वजनिक धन और सार्वजनिक हितों का है ऐसे में ऐसी गंभीर लापरवाही या जानबूझकर की गई गलती है के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। वहीं आम जनता द्वारा इस प्रकार के मामले में विभागीय ऑडिट के अलावा सोशल ऑडिट का विकल्प भी अपनाया जाना चाहिए। ताकि भविष्य में इस प्रकार आम जनता के धन का दुरुपयोग न हो। वही देश की स्वच्छता का सिरमौर इंदौर शहर अपनी बाहरी स्वच्छता के साथ ही आंतरिक स्वच्छता में भी देश में अपनी अलग पहचान बनाएं।

राम मंदिर दान चोरी प्रकरण: आरोपी पुलिस रिमांड में, कई खुलासों की उम्मीद

अयोध्या।

राम मंदिर में दान राशि चोरी के मामले में पुलिस को तीन आरोपियों की अभिरक्षा रिमांड मिल गई है, जिससे प्रकरण से जुड़े कई नए तथ्य सामने आने की संभावना है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पाण्डेय को मंगलवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने 40 घंटे की पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर भेजा है।

पुलिस ने न्यायालय से सात दिन की रिमांड की मांग करते हुए कहा था कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं तथा आरोपियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर नए साक्ष्य और अन्य वस्तुओं की बरामदगी आवश्यक है। पुलिस अब आरोपियों से दान राशि कहां खर्च की गई, चोरी किस प्रकार की गई और राशि या अन्य सामग्री कहां छिपाई गई, जैसे बिंदुओं पर गहन पूछताछ करेगी।

मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। विशेष जांच दल की प्रारंभिक प्रतिवेदन और निर्देशों के आधार पर आठ लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

इससे पूर्व न्यायालय के निर्देश पर पुलिस जेल में भी आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ कर चुकी है। एक आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लेकर एक कार सहित कई वस्तुओं की बरामदगी भी की जा चुकी है। अब तीन अन्य प्रमुख आरोपियों की रिमांड मिलने से जांच में और तेजी आने की उम्मीद है।

मामले के विवेचक एवं क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने न्यायालय में उपस्थित रहकर पुलिस का पक्ष रखा, जबकि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता कुलशेखर सिंह ने रिमांड आवेदन का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पुलिस की मांग स्वीकार करते हुए लगभग 40 घंटे की अभिरक्षा रिमांड मंजूर कर ली।

बुधवार सुबह पुलिस तीनों आरोपियों को जेल से रिमांड पर लेकर आई। इससे पहले 5 जुलाई को भी न्यायालय की अनुमति से पुलिस ने जेल में करीब पांच घंटे तक उनसे गहन पूछताछ की थी। उस दौरान आरोपियों के मोबाइल संदेशों की जांच में कई नई जानकारियां सामने आई थीं, जिनका सत्यापन भी कराया गया।

पुलिस ने आरोपियों से अलग-अलग तथा आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ की थी। अब अभिरक्षा रिमांड के दौरान उनकी निशानदेही पर नए साक्ष्य, डिजिटल प्रमाण और अन्य संभावित बरामदगी की कार्रवाई की जाएगी।

बदरीनाथ चढ़ावा प्रकरण: मंदिर समिति के कर्मचारी निलंबित

देहरादून।

बदरीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने पांच दिन बाद पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में चढ़ावे में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।

मुख्यमंत्री च्नेींतं पदही कींउप ने जांच समिति को 15 दिनों के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख डंलूंजप ने भी मामले की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की है।

मंदिर समिति के अनुसार प्रमोद नौटियाल पर प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताओं के आरोप पाए गए हैं। समिति का कहना है कि उनके वर्तमान पद पर बने रहने से जांच प्रभावित हो सकती थी। इसी कारण 3 जुलाई को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करने के बाद उन्हें

निलंबित किया गया। हालांकि समिति अध्यक्ष भ्मउंदज कूपअमकप ने स्पष्ट किया कि नौटियाल उनके निजी सचिव नहीं, बल्कि समिति के कर्मचारी थे।

बदरीनाथ क्षेत्र के विधायक ैंाीचंज ठनजवसं ने मौन धरना देकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि चढ़ावे में कथित अनियमितता अत्यंत गंभीर विषय है और इसकी जांच उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश की निगरानी में कराई जानी चाहिए। उन्होंने जांच प्रतिवेदन सार्वजनिक करने की भी मांग की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। विधायक ने मंदिर के कपाट खुलने के दिन से अब तक की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की मांग भी की है।

सरकारी अस्पतालों में करोड़ों की चिकित्सा मशीनें निष्क्रिय, न्यायालय सख्त

नई दिल्ली।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर खरीदी गई कई महंगी चिकित्सा मशीनें वर्षों से उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं। इससे न केवल मरीजों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, बल्कि सरकारी धन का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उच्च न्यायालय ने इसे जनता के धन की बर्बादी बताते हुए दिल्ली सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों को ऐसी मशीनों की जांच कराने का निर्देश दिया है, जो खरीदी तो गईं लेकिन उपयोग में नहीं लाई जा रहीं।

न्यायालय के समक्ष दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान की 15.42 करोड़ रुपए लागत वाली पीईटी साइक्लोट्रॉन मशीन का मामला आया था, जो अप्रैल 2022 से बंद पड़ी है। इसके बाद न्यायालय ने सभी अस्पतालों में ऐसी मशीनों का लेखा परीक्षण कराने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी अस्पताल यह जानकारी एकत्र करें कि कौन-कौन सी मशीनें खरीदी गईं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। प्रत्येक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को इस संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक धन से खरीदी गई चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके और सरकारी संसाधनों का उचित उपयोग हो।

बड़ी सफलता: लश्कर का शीर्ष कमांडर मारा गया

जम्मू।

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर जाकिर गनी को मार गिराया है। अधिकारियों के अनुसार शनिवार को शुरू किए गए अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ के चार दिन बाद घटनास्थल से उसका शव बरामद किया गया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जाकिर गनी पहलगाम आतंकी हमले से भी जुड़ा हुआ था और लंबे समय से सुरक्षा बलों की तलाश में था।

अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान गोलीबारी की आवाजें सुनाई देने के बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की थी। इसके बाद क्षेत्र में लगातार सघन तलाशी अभियान चलाया गया। मंगलवार को तलाशी के दौरान एक शव बरामद हुआ। घटनास्थल से हथियार और गोला-बारूद भी मिले हैं। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुष्टि हुई कि मारा गया आतंकी जाकिर गनी था।

शोपियां जिला लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता रहा है। यह इलाका लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ जैसे संगठनों के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। दक्षिण कश्मीर को पीर पंजाल पर्वतमाला से जोड़ने वाला यह क्षेत्र घने सेब बागानों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आतंकियों के छिपने तथा आवाजाही का मार्ग रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में शोपियां में आतंकियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, बाहरी श्रमिकों तथा सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं। इन घटनाओं को देखते हुए भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विक्टर फोर्स सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र में लगातार संयुक्त अभियान चला रही हैं।

सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि जाकिर गनी के मारे जाने से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

इंदौर से भोपाल तक निकलेगी कांग्रेस की साइकिल यात्रा

भोपाल।

कांग्रेस 14 जुलाई से इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ प्रत्येक जिले से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। इंदौर में शहर कांग्रेस की ओर से लगभग दो हजार साइकिल सवार यात्रा का हिस्सा बनेंगे। हालांकि जीतू पटवारी इंदौर से भोपाल तक पूरी यात्रा साइकिल से तय करेंगे।

यात्रा की शुरुआत 14 जुलाई को सुबह 7 बजे आरएनटी मार्ग स्थित विश्वविद्यालय परिसर से होगी। कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मोहल्ला और वार्ड स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने बताया कि साइकिल यात्रा विश्वविद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर रीगल चौराहा, उच्च न्यायालय चौराहा, लैंटर्न चौराहा, मालवा मिल चौराहा, सयाजी चौराहा, विजय नगर, सत्यसाईं चौराहा, देवास नाका, लसूड़िया, बायपास मोड़, मांगलिया, डकाच्या और शिप्रा होते हुए देवास जिले की सीमा में प्रवेश करेगी।

शहर कांग्रेस के कार्यकर्ता साइकिल चलाते हुए जीतू पटवारी को इंदौर शहर की सीमा तक छोड़ने जाएंगे। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यात्रा में शामिल रहेंगे।

करोड़ों की गड़बड़ी, न एफआईआर न विभागीय कार्रवाई

भोपाल।

मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एमपीटी) में करीब 3.91 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के दो माह बाद भी न तो पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और न ही निगम ने किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की है। इससे निगम की वित्तीय निगरानी और जवाबदेही पर प्रश्न उठने लगे हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यह कथित अनियमितता वर्ष 2022-23 से फरवरी 2026 तक लगातार होती रही, तो प्रत्येक वर्ष होने वाले लेखा परीक्षण में इसका खुलासा क्यों नहीं हुआ। करोड़ों रुपए निगम के खाते में जमा नहीं हुए, इसके बावजूद किसी स्तर पर इसकी जानकारी सामने नहीं आना लेखा परीक्षण व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

उल्लेखनीय है कि कुछ माह पहले 26 लाख रुपए की वित्तीय गड़बड़ी के मामले में निगम ने दो अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया था, जबकि लगभग चार करोड़ रुपए के इस मामले में अब तक किसी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है।

एमपीटी के कंपनी सचिव संदेश यशलहा के अनुसार निगम ने जांच प्रतिवेदन तैयार कर कमला नगर थाने को सौंप दिया है तथा प्रकरण दर्ज करने का अनुरोध भी किया है। वहीं मामले की जांच कर रहे उपनिरीक्षक शैलेंद्र सिंह राजावत का कहना है कि निगम की रिपोर्ट में कई तथ्य स्पष्ट नहीं हैं। जिस आउटसोर्स कर्मचारी को जिम्मेदार बताया गया है, उससे पूछताछ की जा चुकी है। जिन ग्राहकों के नाम पर भुगतान दर्शाया गया है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। सभी दस्तावेजों और तथ्यों के सत्यापन के बाद ही प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

जांच के अनुसार विपणन शाखा में कार्यरत विपणन कार्यकारी पीयूष कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने होटल और जंगल सफारी बुकिंग के दौरान ग्राहकों से प्राप्त राशि निगम के खाते में जमा कराने के बजाय अपने निजी खाते में स्थानांतरित कर ली। जांच में यह भी सामने आया कि जूबो सॉफ्टवेयर में दो प्रकार की रसीदें बनाई जाती थीं। एक श्रेणी की राशि नियमित रूप से निगम के खाते में जमा होती थी, जबकि दूसरी श्रेणी की राशि बैंक में जमा ही नहीं की गई। ग्राहकों को सेवाएं मिलती रहीं, इसलिए यह कथित गड़बड़ी लंबे समय तक सामने नहीं आ सकी। वर्ष 2022-23 में 39.16 लाख रुपए, वर्ष 2023-24 में 56.13 लाख रुपए, वर्ष 2024-25 में 1.19 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2025-26 में फरवरी तक 1.76 करोड़ रुपए की कथित अनियमितता सामने आई है। इस प्रकार कुल राशि 3.91 करोड़ रुपए बताई गई है।

नगरपालिका परिषद सम्मेलन की उधेड़-बुन के बाद 2025 में पारित हुआ पीपीपी मॉडल फिर से पारित

समर्थन और विरोध के भारी हंगामें के बाद भी 13 दुकानदारों का भविष्य अब भी संदेह के घेरे में

माही की गूंज, झाबुआ।

पिछले एक माह से नगर में चल रही धर्मशाला भवन पुनर्निमाण की गुत्थम गुत्था सोमवार को हुए नगरपालिका परिषद सम्मेलन के बाद शांत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके नगरपालिका परिषद का यह सम्मेलन कई सवालों को जन्म देता दिखाई दे रहा है। बस स्टेंड के समीप धर्मशाला भवन जो कि जर्जर हो चुका है, इस भवन में बनी 13 दुकानों को नगरपालिका ने करीब एक माह पूर्व सील कर दिया था। सतत लगभग एक माह से नगरपालिका और व्यापारियों के बीच गहमा -गहमी वाली स्थिति निर्मित रही। लेकिन 6 जुलाई को हुए नगरपालिका परिषद के सम्मेलन के बाद भी व्यापारियों को कोई खास राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि सम्मेलन में यह बात जरूर रखी गई कि, निर्माण के बाद पुराने 13 दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन जिस पीपीपी मॉडल से काम्प्लेक्स का निर्माण तय हुआ है उसकी नियम और शर्तों ने व्यापारियों के भविष्य पर अब भी प्रश्न वाचक चिन्ह लगा रखा है।

नगरपालिका द्वारा धर्मशाला भवन की 13 दुकानों को सील करने के बाद से ही यहां के व्यापारियों सहित व्यापारी संघ ने विरोध शुरू कर दिया था। लगभग एक महिना व्यापारियों और नगरपालिका के बीच जमकर गहमा-गहमी चली। मगर नगरपालिका और व्यापारियों के बीच कोई सीधा हल समस्या का नहीं निकल सका। दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी बात को लेकर अड़े हुए दिखाई दिए। लंबी कवायद के बाद नगरपालिका ने इस मुद्दे को लेकर नगरपालिका परिषद सम्मेलन का आयोजन किया। 6 जुलाई को हुए नगरपालिका परिषद के इस सम्मेलन में जबरदस्त नौटंकी देखने को मिली। सुबह साढ़े 11 बजे से ही नगरपालिका परिषद सम्मेलन में जमकर हंगामा देखने को मिला। कहा-सुनी और तर्क -कुतर्क के बीच माहौल जमकर गर्माता दिखाई दिया। स्थिति को देखते हुए सीएमओ द्वारा तहसीलदार और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद तहसीलदार और पुलिस, नगर पालिका पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया परिस्थितियां सामान्य सी देखकर वे वापस लौट गए।

नगरपालिका के इस सम्मेलन में लंबी बहस और तर्क-कुतर्क के साथ पीपीपी मॉडल पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने पर बहुमत मिल गया और सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास हो गया। सम्मेलन में इस प्रस्ताव के पक्ष में परिषद के 10 पार्षद रहे तो विरोध में 8 पार्षदों ने अपना पक्ष रखा। बताया जाता है कि, समर्थन करने वाले अधिकतर पार्षद भाजपा खेमे के है तो विरोध करने वाले पार्षदों में कांग्रेस खेमे के पार्षद ज्यादा है। मगर इन सब के बीच नगरपालिका अध्यक्ष ने व्यापारियों के पक्ष में आते हुए पीपीपी मॉडल के विरोध में अपना मत रखा है। नगरपालिका अध्यक्ष भाजपा से आती है मगर इस सम्मेलन में वे भाजपाई खेमे के पार्षदों से अलग दिखाई दी। लोग इस घटनाक्रम के कई मायने निकालते दिखाई दे रहे है। बताने वाले बताते है कि, अध्यक्ष ने राजनीतिक रूख अपनाते हुए व्यापारियों का साथ दिया ताकि व्यापारियो के साथ किसी तरह का बिगाड़ न हो और परिषद में बैठे उन्ही के खेमे के भाजपा पार्षदों को व्यापारियों के खिलाफ एक जुट कर प्रस्ताव पारित करवा दिया। यानि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।

बताने वाले बताते है कि, नगरपालिका परिषद का यह सम्मेलन पूरी तरह से नौटंकी ही था। क्योंकि जिस प्रस्ताव को लेकर नगरपालिका परिषद ने यह सम्मेलन आयोजित किया था वह प्रस्ताव तो 2025 में ही पारित हो चुका है। नगरपालिका के रिकार्ड के अनुसार 4 अगस्त 2025 को ही प्रस्ताव संकल्प क्रमांक 227 के माध्यम से पंडित नेहरू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे की रिक्त भूमि को मध्यप्रदेश अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 अथवा पीपीपी मोड के अंतर्गत आवंटित करने का निर्णय लिया जा चुका था। उस समय यह तर्क रखा गया था कि, रिक्त स्थल अनुपयोगी होकर वहां गंदगी हो रही है। निकाय की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है जिसके कारण कर्मचारियों के वेतन भुगतान, विद्युत बिल और लिए गए ऋणों को चुकानें के लिए अतिरिक्त आय की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव को तब उपस्थित समस्त सदस्यों ने सर्वानुमति से पीपीपी मॉडल के तहत स्वीकृत किया था। इसी प्रस्ताव को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि, कॉम्प्लेक्स को ढहाने और पीपीपी मोड पर बनाने की रूपरेखा पहले ही बन चुकी थी।

जिन पार्षदों ने नगरपालिका परिषद सम्मेलन में इस प्रस्ताव के विरोध में मत रखा है। उनका यह कहना है कि, निर्माण चाहे जैसे भी हो लेकिन पुनर्निमाण के बाद 13 दुकानदारों को सीधे तौर पर दुकानें वापस दी जाए। जबकि पीपीपी मॉडल के तहत अगर यह निर्माण होता है तो इस बात में संषय पैदा हो जाता है कि, यह दुकानें वापस उन्ही व्यापारियों को मिलेंगी जो अभी यहां पर स्थाई रूप से व्यापार कर रहे है? इधर पीपीपी मॉडल मोड पर निर्माण की बात करें तो यह पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशी होती है। जिसमें जमीन सरकारी या नगरपालिका की होती है, लेकिन निर्माण का खर्च और विकास निजी कंपनी या ठेकेदार करता है। इसके बदले में निजी कंपनी या ठेकेदार को एक तय समय तक उस निर्माण से कमाई करने का अधिकार मिलता है। समय सीमा समाप्त होते ही संपत्ती फिर नगरपालिका के अधिपत्य में आ जाती है।

सीधे तौर पर पीपीपी मॉडल मोड से अगर इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तो फिर सीधे तौर पर निर्माण के बाद यह कॉम्प्लेक्स निर्माण एजेंसी के अधिन हो जाएगा। इस स्थिति में नए कॉम्प्लेक्स में पुराने व्यापारियों को नगरपालिका किस तरह से प्राथमिकता दिलवा पाएगी। क्या निर्माण एजेंसी और नगरपालिका के बीच इस तरह का अनुबंध होगा कि, निर्माण के बाद एजेंसी पुराने दुकानदारों को दुकान देने में प्राथमिकता दे? अगर ऐसा नही होता है तो यह शत-प्रतिशत तय है कि, इस कॉम्प्लेक्स में वर्तमान में अपनी दुकान चला रहे 13 दुकानदारों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। या फिर उन्हे निर्माण एजेंसी को मुंह मांगी कीमत दुकानों के लिए अदा करना पड़ेगी। यदि दुकानें निलामी से आवंटित होती है तब फिर पुराने दुकानदारों को प्राथमिकता कैसे दी जाएगी? दोनों ही सूरतों में हासिये पर सिर्फ और सिर्फ व्यापारी ही नजर आता है।

नियमों के अनुसार अगर निर्माण होता है तो यह भी तय है कि, बनने वाले कॉम्प्लेक्स की दुकानों की साइज में कमी आ जाएगी। क्योंकि कॉम्प्लेक्स के पीछे से होकर एक नाला गुजर रहा है। नियमों के अनुसार नाले की उपरी सतह से 9 मीटर तक निर्माण नही हो सकता। ऐसी स्थिति यहां कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जगह बहुत ही कम बचेगी।

6 जुलाई को हुए नगरपालिका परिषद के इस सम्मेलन को देखने और समझने के लिए कॉम्प्लेक्स के तमाम व्यापारी और व्यापारी संघ के पदाधिकारी भी नगरपालिका परिसर में ही मौजूद रहे। बताने वाले बताते है कि, जिन 10 पार्षदों ने पीपीपी मॉडल मोड प्रस्ताव का समर्थन किया उन्होने जनहित और नगरपालिका के रेवेन्यू मॉडल को देखते हुए समर्थन दिया। जबकि व्यापारियों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। जिन 8 पार्षदों ने इसका विरोध किया उन्होने सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों की भलाई और भविष्य को देखते हुए विरोध किया। पूरे दिन के इस सारे झमेले का नतीजा यह निकला कि अगस्त 2025 में ही यह तय हो चुका था कि उंट किस करवट बैठाना है और नगरपालिका परिषद इसमें कामयाब होती भी दिखाई दी है। नगरपालिका परिषद सम्मेलन की उधेड़-बुन के बाद 2025 में पारित हुआ पीपीपी मॉडल मोड फिर से पारित हो गया।

गांव की स्ट्रीट लाइट काफी समय से बंद लेकिन पंचायत नहीं देती ध्यान

माही की गूंज, भामल।
सुनील सोलंकी

थांदला जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत भामल में काफी समय से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां के आमजन को रात्रि में काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर भी जिम्मेदार ग्राम पंचायत के अधिकारी व चुने हुए जनप्रतिनिधि इस और कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि, जब चुनाव था उस समय पर्चे पर बड़े स्लोगन के साथ प्रचार-प्रसार मे वादे किए थे जिसमें गांव के विकास मे प्राथमिकता में स्ट्रीट लाइट पहले रखी गई थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आज दिन तक स्ट्रीट लाइट की तरफ जनप्रतिनिधि द्वारा कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। जिसके कारण आज भी भामल ग्राम मे चौराहे व गांव के अंदर अंधेरे में डूबा हुआ है। पूर्व में जो पंचायत समिति थी जिसमे बद्रीबाई नागु सिंह डामर के समय स्ट्रीट लाइट्स स्वीकृत हुई थी। लेकिन मेंटेनेंस सही से नहीं होने के कारण वह व्यवस्था भी बंद हो गई। जब नई पंचायत समिति बनी तो ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया था कि, गांव में प्राथमिकता से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन 4 साल हो गया नई पंचायत समिति बनने के बाद आज दिन तक गांव की स्ट्रीट लाइट का सही से निर्माण नहीं किया गया।

ग्रामीणों का कहना है कि, चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे तो किए जाते हैं। लेकिन जब धरातल पर कार्य करने की बारी आती है। तो सब जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि, गांव मे स्ट्रीट लाइट जल्द से जल्द शुरू की जाए अभी बारिश का समय है जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियां होती है। वही आने वाले समय में सावन माह में भक्ति मय के साथ ग्रामीण, मंदिरों मे भव्य सुंदरकांड का आयोजन बड़ी उत्साह के साथ करेंगे जिससे रात्रि में काफी चहल पहल रहेगी। अगर समय रहते स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर दी जाती है तो काफी सहूलियत ग्रामीणों को मिल जाएगी। ग्रामीणों की मांग है कि, जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट स्वीकृत करवा कर यहां नए सिरे से स्ट्रीट लाइट लगाई जाए।

12 लाख से अधिक की लागत से बनाया जा रहा उचित मूल्य दुकान का गोदाम

ग्राम भामल में ही मादलदा रोड पर 8 वे पुल के समीप एक शासकीय उचित मूल्य की दुकान का गोदाम बनाया जा रहा है। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत है और उसके द्वारा ही धरातल पर कार्य करवाया जा रहा है। कार्य की गुणवता को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि, एक बार विभागीय अधिकारियों को यहा निरीक्षण करना चाहिए। क्योंकि ग्राम पंचायत भामल में कई जगह अनियमिताओ का अम्बार लगा हुआ है। जहां भी धरातल पर सरकारी कार्य किया जा रहा है, वहां पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं है। जिससे आम जनता को उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही हैं। पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम भामल में कई पुल-पुलिया के साथ नाली निर्माण व सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन कभी भी यहां संबंधित इंजीनियर मूल्यांकन करने नहीं पहुंचा। जिससे कहीं ना कहीं कार्य में अनियमिताओं का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं की विभागीय अधिकारी व इंजीनियर की मिली भगत से कार्य को भ्रष्टाचार के रूप में अंजाम दिया जा रहा है। अगर झाबुआ जिले के वरिष्ठ अधिकारी इस और ध्यान देवे तो काफी अनियमिता पंचायत में उजागर हो सकती है। तो वहीं जहां आबादी क्षेत्र में नाली बनना चाहिए वहां नाली न बनाते हुए खेत में नाली पंचायत द्वारा बनाई जा रही है। जबकि उसको आबादी क्षेत्र में बनाने का प्रावधान है। वहां ना बनाते हुए खेत में नाली बनाई जा रही है। इस और भी वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान देकर मामले में जांच करनी चाहिए। वहीं जहां भी निर्माण कार्य किया जा रहे हैं। वहां साइन बोर्ड पंचायत द्वारा नहीं लगाई जा रहे हैं। जबकी मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित निर्माण कार्यों में स्थल पर ''साइन बोर्ड'' लगाना अनिवार्य है, नियमों और पारदर्शिता दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्माण स्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड (सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड) लगाना आवश्यक है, ताकि आम जनता को कार्य की पूरी जानकारी मिल सके पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन बोर्डों को लगवाने के स्पष्ट निर्देश हैं (अक्सर कलेक्टर द्वारा भी इसकी समीक्षा की जाती है) साइन बोर्ड न होने पर ग्राम पंचायत और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है। और ऑडिट में इसे अनियमितता माना जाता है। यहां धरातल पर कहीं भी सरकारी कार्य में कोई भी साइन बोर्ड लगा हुआ नजर नहीं आता है। जिससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जा रही है। यह ग्रामीणों का कहना। वही पंचायत राज्य दर्पण पर कई बिल ऐसे लगाए जा रहे हैं। जो पंचायत द्वारा जिसकी कोई फर्म ही नहीं है। और ना ही उनके द्वारा कभी रेत गिट्टी वह पानी सप्लाई का कार्य किया भी नहीं जाता है। सिर्फ बिल लगाकर पैसे आहरण करने की योजना पंचायत ने बना रखी है।

वादेकर कर जिते पर वादे अब भी अधुरे

कचरा संग्रहण के लिए बनाए गए शेड के चद्दर तक गायब हो गए लेकिन पंचायत ने नहीं की कोई कार्रवाई

ग्राम भामल काफी समय से वीरान पड़े कचरा संग्रहण के लिए शेड को लावारिस हालत में देखते हुए अज्ञात चोरों ने वहां के चदर तक गायब कर दिए बताते है। बताते है की स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम भामल में एक इलेक्ट्रिकल टेंपो दिया गया था। जिसमें सूखा हुआ गीला कचरा संग्रहित करके अपशिष्ट पदार्थ बनाना था लेकिन वह आज भी लावारिस हालत में पड़ा है और आज भी गांव में टेम्पू की स्थति काफी खराब हो गईं सही रख रखाव व मेंटनेस नहीं होने के कारण कचरा सग्रहण शेड व टेम्पू लावारिस हालत मे पड़े है।

← पंचायत दर्पण 5.8

इस तरह से कबूतर बिल लगाए जा रहे है पंचायत दर्पण पोर्टल पर जिसकी धरातल पर कोई ऐसी दुकान ही नहीं है।

12 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा शासकीय उचित मूल्य की दुकान का गोदाम जो निम्न स्तर का कार्य हो रहा है।

कचरा संग्रहण के लिए बनाया गया जो शेड उसके ऊपर से चद्दर तक गायब हो गए है।

भारतीय समाज पर संकट घुसपैठिए राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं, यह राष्ट्र का मुद्दा है

माही की गूंज, झाबुआ।

भारत-बांग्लादेश की सीमा दुनिया की पांचवी सबसे लंबी सीमा है, यह सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है, इस सीमा में घने जंगल, पहाड़, नदियां है, और यहीं से लाखों की संख्या में घुसपैठिए प्रतिवर्ष भारत की सीमा में प्रवेश करते है। चिंताजनक बात यह है कि, वर्तमान में तीन से पांच करोड़ घुसपैठिए भारत देश में अवैधरुप से निवासरत हैं। बाग्लादेशी और रोहिग्या घुसपैठिए देश की संप्रभुता के लिए खतरा है, इन घुसपैठियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था एक बहुत बड़े संकट के घेरे में है, वहीं बीते कुछ समय से रोहिग्या घुसपैठियों ने इस समस्या से उपजे संकट को और भी अधिक गंभीर रुप दे दिया है।

अपने देश से घुसपैठियों को निकालना राजनीति पार्टियों के लिए एजेंडा कैसे बन जाता है जबकि यह अपने आप में ही राष्ट्र का मुद्दा है। घुसपैठियों को भारत से डिपोर्ट करके निकालने की सरकार की योजना को अन्य राजनीतिक पार्टिया भाजपा का एजेंडा कहकर भारतीय जनता को भ्रमीत कर रही है जबकि घुसपैठिए भारतीय संसाधनों पर कब्जा किए हुए है, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। विश्व के अन्य देश अपनी जनता का साथ देते हुए घुसपैठियों को बाहर भगा रहे हैं और वहां के राजनीति दल इस बात पर बहस न करते हुए बिनी किसी विरोध में एक सहमत हो रहे हैं तो भारत में राष्ट्र के मुद्दे पर सभी राजनीति दल एक मत क्यों नहीं होते हैं।

जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने 1 लाख 46 हजार अफगानिस्तानी घुसपैठियों को यह कह कर देश से निकाल दिया कि, ये घुसपैठिए हमारे संसाधनों को समाप्त कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और अफगानिस्तान के जो घुसपैठिए है वो भी मुसलमान है। इसी तरह मुस्लिम देश ईरान ने जून 2025 से फरवरी 2026 तक अफगानिस्तान के 15 लाख घुसपैठियों को उनके देश भेज दिया। युएई ने 7 हजार 500 शिया पाकिस्तानी घुसपैठियों को देश से बाहर कर दिया क्योंकि, संसाधनों के साथ ये पाकिस्तानी घुसपैठिए ईरान की मदद कर रहे थे। सउदी अरब ने 18 हजार 836 घुसपैठिए बाहर किए जिसमें 60 प्रतिशत मुस्लिम देश इथियोपिया के, 39 प्रतिशत गेलन के थे जो कि सभी मुस्लिम हैं। तुर्किया ने 2 लाख 60 हजार और जार्डन ने 1 लाख 75 हजार पाकिस्तानी, सिरिया, फिलीस्तानी घुसपैठियों को अपने मुस्लिम देश से बाहर कर दिया।

इन आंकड़ों को देख कर लगता है कि, मुस्लिम देश अपने क्षेत्र में घुसे मुस्लिम घुसपैठियों को देश से निकाल दे तो किसी को कोई समस्या नहीं मानव अधिकार वाले भी अपने मुंह पर पट्टी लगाकर घुमते हैं। परंतु भारत ने लॉ ऑफ लेंड के तहत घुसपैठियों को बाहर करने की शुरुआत की तो विपक्ष से लगाकर मानव अधिकार तक अधिकार की आवाज उछलने लगी। फिर जब अधिकार की बात की जाए तब पहला अधिकार देश पर उस देश के मूलनिवासियों का होता है, घुसपैठियों का नहीं।

देश की संप्रभूता के लिए संकट घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे सिंडिकेट के उन्मुलन और घुसपैठ रोकने के उपाय देश में हो रही गंदी राजनीति के भेट चढ़ गए। सीमा के इस पार और उस पार यहां तक कि, सीमा के अंदर भी तस्करो का नेटवर्क शक्ति के साथ काम कर रहा है जिनको राजनीतिक संरक्षण है। भारतीय सीमा शुरु से ही घुसपैठ से संक्रमित है, 4096 किलोमीटर लंबी बार्डर जहां पहाड़, जंगल, नदियां हो वहां से बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना गंभीर समस्या तो है ही यह हमारी सुरक्षा के लिए भी घातक है, इससे हमारी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था प्रभावशील होकर दुष्प्रचारित होती है। 2003-04 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की 25 लोकसभा सीटें और 120 विधानसभा सीटों को बांग्लादेशी घुसपैठिये प्रभावित करते हैं। 2003 तक दिल्ली में 6 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भारतीय पहचान पत्र बनवा लिए थे। अनुमान है कि, देश के अन्य राज्यों में भी इनकी स्थिति इसी तरह गंभीर बनी हुई है क्योंकि, वर्तमान में पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठिये तीन से पांच करोड़ हो चुके है, जिसमें से बहुत से अनैतिक, गैरकानूनी और अवैध गतिविधियों में सम्मिलित होकर सक्रिय रहते हैं।

मुस्लिम देश मुस्लिम घुसपैठियों को निकाले तो ठीक परंतु भारत देश से घुसपैठियों को निकालने लगे तो यह भाजपा पार्टी का एजेंडा कैसे हो जाता है। पश्चिम बंगाल के हलिमपुर में टीएमसी की सीट पर खड़े प्रत्याशियों की जीत हुई है, और यह वह स्थान है जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा रहते हैं। पूरे देश में घुसपैठिए यह देखते हैं कि उनको सरकारी योजना का लाभ कहां पर कितनी जल्दी और कितना आसानी से मिल जाएगा, इसलिए ये घुसपैठिए महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम जैसे राज्यों में पहले पहुंचते हैं।

रिंकेश बैरागी

2002 में कोलकाता से बहुत से आइएसआइ एजेंटो की गिरफ्तारी के बाद भारत के तत्कालिन विदेश मंत्री यशवंत सिंह ने संसद में कहा था कि, ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिशन आइएसआइ का नर्व सेंटर है जो भारत के विरुद्ध आंतकी गतिविधियों में लिप्त है। अक्तूबर 2002 में बीएसएफ ने बांग्लादेश बार्डर गार्डस् को बांग्लादेश में चल रहें, 99 आंतकी ट्रेनींग केंप की लिस्ट सौंपी थी।

भारत के प्रधानमंत्री, और गृहमंत्री दोनों चुनावी दंगल में घुसपैठियों को देश से बाहर निकलने की बात पर जोर दिया था। जहां-जहां घुसपैठियें बस जाते हैं वहां छोटे व्यवसाइयों और स्थानीय निवासियों की आजीविका पर कब्जा कर लेते हैं। असम में ही एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए देश के गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत देश कोई धर्मशाला नहीं है, इसीलिए घुसपैठियों के लिए यहां कोई जगह नहीं है।

देश के लिए घुसपैठिए कितने हानिकारक है यह जानते हुए भी राजनीति दल घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एकमत नहीं हो रहे हैं। जब मुस्लिम देश अपने देश में से मुस्लिम घुसपैठियों को बार कर सकते हैं तब भारत इस तरफ कदम बढ़ाता है तो अन्य दलों को भी गंभीरता के साथ सरकार का साथ देना चाहिए।

ग्राम सेवक भवन खोलेगा सरकारी संपत्ती को खरीद फरोख्त का राज

शिकायत की जांच जारी, कब्जेधारी को थमाया नोटिस, पहचान मिटाने की कोशिश

ग्राम सेवक भवन सारंगी।

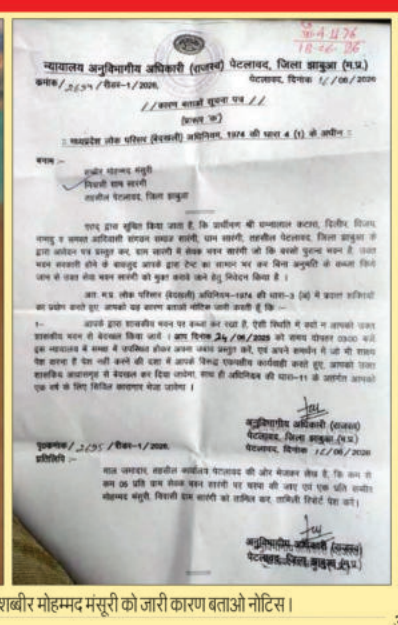

शिकायत के बार शब्बीर मोहम्मद मंसूरी को जारी कारण बताओ नोटिस।

भवन पर दर्ज नाम।

पहचान मिटाने की कोशिश ,नाम हटाकर गारा पोत दिया गया।

माही की गूंज, पेटलावद।

विकास खंड पेटलावद की सबसे ज्यादा राजस्व आय वाली ग्राम पंचायत सारंगी का अवैध पट्टा वितरण कांड अभी ठंडा भी नहीं हुआ की, एक और मामला सरकारी संपत्ति को बेचने का बहार आ गया है। बता दे ग्राम ग्राम पंचायत सारंगी सरपंच, सचिव ओर उप सरपंच पर शासकीय भूमि को पट्टे के नाम पर विक्रय करने के गंभीर आरोपों की जांच चल रही है। विगत दिनों सारंगी में आयोजित विशेष जनसुनवाई कार्यक्रम में सारंगी धन्नालाल कटारा, दिलीप, नंदू आदि ने सारंगी में स्थित पुराना शासकीय ग्राम सेवक भवन पर अवैध रूप से कब्जे की शिकायत दर्ज करवाई, जिसकी जांच की जा रही है। ओर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस शासकीय भवन को कब्जे के नाम पर बेचा गया है जिसके बाद गांव के ही शब्बीर मोहम्मद मंसूरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।

एसडीएम के पास जांच, शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत पर की आशंका व्यक्त

पेटलावद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तनु श्री मीणा के पास पट्टे की जांच के बाद सारंगी के इस सरकारी भवन के कब्जे का मामला पहुंचा । शिकायत के बाद सारंगी निवासी शब्बीर मोहम्मद मंसूरी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय से मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1974 की धार 3-(अ) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है । बताया जा रहा है उक्त भवन में टेंट का कुछ सामान ओर ताला अन्य किसी व्यक्ति का लगा पाया गया। जांच के दौरान किसी ने भी उक्त ताले ओर सामान की जिम्मेदारी नहीं ली। शिकायतकर्ता धन्नालाल कटारा ने बताया कि उक्त भूमि ओर मकान शासकीय मद का है ओर अन्य व्यक्ति द्वारा इस पर कब्जा कर रखा है हमको पूरी आशंका है कि उक्त सरकारी संपत्ति की खरीद फरोख्त लाखों में की गई है और ग्राम पंचायत का इसमें हाथ हो सकता है जिसकी जांच की जानी चाहिए ।

ड्रोन सर्वे में भी भवन शासकीय, पहचान मिटाने की कोशिश

शासकीय राजस्व रिकॉड की जानकारी जुटाने पर ग्राम सेवक भवन की स्थिति का पता किया तो जानकारी मिली कि ड्रोन सर्वे में भी उक्त भवन शासकीय दर्ज किया गया है । भवन के फोटो में साफ दिखाई दे रहा है कि भवन पर नाम की पुराने जमाने की नाम प्लेट लगी है जिस पर सारंगी ग्राम सेवक भवन लिखा हुआ है, जबकि दूसरे फोटो में इस भवन की पहचान मिटाने की कोशिश की गई है, भवन पर लगी प्लेट को हटा कर वहा गारे से लिपा पोती कर दी गई है। मामले में जिस पक्ष शब्बीर मोहम्मद मंसूरी को नोटिस जारी हुआ है उनसे जब हमने इसकी जानकारी ली तो उन्होंने इस भवन पर अपना किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं होना बताया ।

क्या प्रशासन कब्जे में लेगा भवन

मामले में एक पक्ष का आरोप है कि भवन पर अवैध कब्जा है, जांच में भवन पर लगे ताले ओर अंदर रखे सामन किसका है इसकी किसी ने भी जवाबदारी नहीं ली है। वहीं जिसको अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से नोटिस जारी हुआ उसने भी अपना कब्जा होने से पल्ला झाड़ लिया। ऐसी स्थिति में क्या प्रशासन उक्त सरकारी संपत्ति को कब्जे लेकर अपने अधीन करेगा या मामले को जांच के नाम पर घुमाया जाएगा। एक मात्र संपत्ति नहीं है जो शासकीय होकर किसी के कब्जे में है नगर में इस प्रकार की कई संपत्ति है जिसकी जांच होना जरूरी है।

घर पर पत्नी बीमार होने के कारण अस्पताल गया परिवार इधर सुने घर को देख कर चोरों ने किया हाथ साफ

माही की गूंज, खवासा।

खवासा के ही बामनिया रोड स्थित बड़े तालाब क्षेत्र में सोमवार रात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए बदमाश मकान के पिछले हिस्से की दीवार तोड़कर अंदर घुस पलंग पेटी का ताला तोड़कर करीब 500 ग्राम चांदी के जेवर चोरी करके ले गए। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब सवा लाख रुपए बताई जा रही है।

मकान मालिक राकेश डिंडोर ने बताया कि, पत्नी की डिलीवरी के कारण वे शासकीय अस्पताल पेटलावद में गए थे और रात्रि में घर सुना होने का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया मंगलवार सुबह जब हम अस्पताल से छुट्टी होने के बाद घर पहुंचे तो सामान बिखरा मिला, पीछे की दीवार टूटी थी, चांदी के जेवर व नगदी गायब थे। राकेश डिंडोर ने खवासा पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद सूचना मिलते ही खवासा चोकी से पुलिस पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करके आसपास से जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इधर क्षेत्र में हो रही लगातार चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने रात में पुलिस गस्त बढ़ाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वही मामले मे खवासा पुलिस चौकी पर पदस्थ सहायक उप निरीक्षक हरीसिंग मुवेल ने जानकारी देते हुए बताया कि, मौके पर निरीक्षण किया गया है। 40 हजार रुपए की एक चांदी की साकली अज्ञात चोर ले गए हैं। फरियादी, अपनी पत्नी की डिलीवरी होने के कारण पेटलावद अस्पताल में थे और अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है, मामले की जांच की जा रही है अज्ञात चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

नगर का मुख्य भाग्याखाली नाला अतिक्रमण की चपेट में, धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर

माही की गूंज, पेटलावद।

नगर परिषद की लापरवाही कहे की अतिक्रमणकर्ताओ को मौन स्वीकृति नगर में अवैध रूप से होने वाले अतिक्रमण की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात नगर परिषद सड़क पर खड़े हाथ ठेले तो दल बल के साथ हटाने के लिए उतर जाती है लेकिन नगर में हो रहे पक्के अतिक्रमण की ओर कोई देखने को तैयार नहीं है। नगर के थांदला मार्ग पर स्थित प्रेम सागर गार्डन के पास नगर का मुख्य भाग्या खाली नाला मौजूद है जिससे नगर के कई इलाकों का नालियों का पानी इस बड़े नाले से होकर गुजरता है ,बरसात का भी पानी नगर के कई हिस्सों का इस नाले से निकलता है । एक समय ये भाग्या खाली नाला अपने पूरे अस्तित्व में था लेकिन धीरे धीरे इस नाले के पास की जमीनों पर निर्माण शुरू हुआ ओर देखते ही देखते बड़ा नाला एक नाली बन कर रह गया । हालांकि नाले के आसपास आज भी निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है जिसे रोकने वाला कोई नहीं है।

राजस्व रिकॉड में दर्ज नाले का रकबा हुआ खत्म

उक्त नाला राजस्व रिकॉड में भी दर्ज है और रिकॉड में दर्ज मौके रकबे की जांच की तो नाले की जमीन के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण कर निर्माण कर दिया गया है और अवैध रूप कब्जा किया जा चुका है। पूर्व में भी इस मामले में राजस्व विभाग में नगर के एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी जिसकी जांच में नाले की जमीन पर अतिक्रमण पाया गया था जिसे बाद में हटाया गया था लेकिन अतिक्रमणकारता यही नहीं रुके नाले की भूमि पर अतिक्रमण जारी रखते हुए धीरे धीरे नाले की वास्तविकता को समाप्त करने में लगे हुए है।

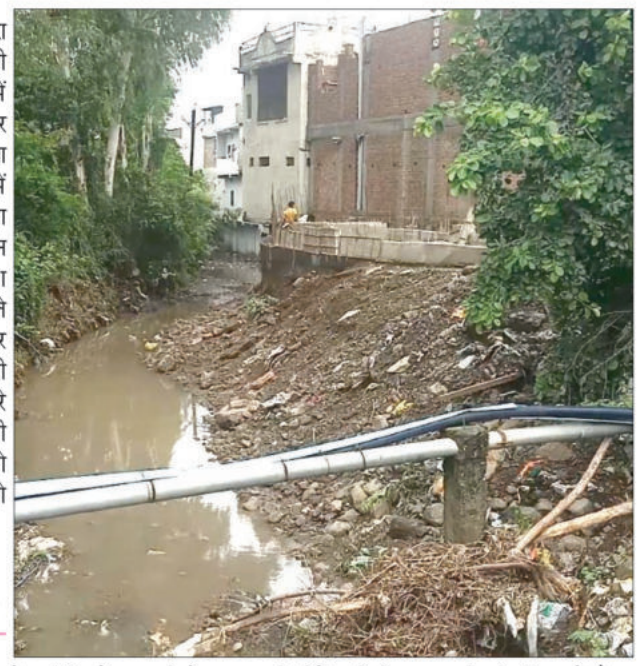

नाले की भूमि पर अतिक्रमण

मुख्य नाला नगर के कई हिस्सों का पानी लेकर थांदला मार्ग से होकर बामनिया मार्ग से होते हुए दुलाखेड़ी की ओर निकलता है। नाले के पीछे वाले क्षेत्र में अलग अलग हिस्सों निजी मकान और कालोनियां काटी जा चुकी हैं ओर नाले की जमीन पर खेत का जाने का रास्ता बता कर कही पुल ते कही सीमेंट की दीवार बना दी गई , जिस को जैसा लगा उसने नाले की भूमि पर निर्माण कर नाले की चौड़ाई लगभग खत्म कर दी । राजस्व रिकॉड के अनुसार नाले के रकबे के अनुसार की जांच की जाए तो नाले पर बड़े अतिक्रमण का मामला उजागर होगा।

रूपगढ़-मोहनकोट मार्ग पर हुए हादसे में दो की मौत, एक गंभीर

माही की गूंज ,पेटलावद।

रूपगढ़-मोहनकोट मार्ग पर माही नहर की पुलिया के पास सोमवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान विदेश पिता देवचंद गुंडिया और अरुण पिता सेतु भाभर (निवासी खेरियापाड़ा) खवासा क्षेत्र के रूप में हुई है। वहीं, विष्णु शांतिलाल गुंडिया गंभीर रूप से घायल है, जिसे झाबुआ रेफर किया गया है। तीनों युवक सोमवार दोपहर नंदर माता दर्शन के लिए निकले थे। रात भर घर न लौटने पर परिजन मंगलवार की सुबह उनकी तलाश में निकले, तब घटना का पता चला। दोनों मृतक विवाहित थे और उनके छोटे बच्चे भी हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपर्द कर दिए। फिलहाल हादसे की सही वजह का पता नहीं लगा है कि किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है या गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी या कोई ओर मामला है , पेटलावद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। युवकों की असामयिक मौत से परिवार में ओर गांव में शोक छा गया, मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।

गोल घेरे में दुर्घटना ग्रस्त बाईक।

गंदे पानी के बीच से निकलकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं 1500 बच्चे

माही की गूंज, धार/बदनावर।

कंधों पर बस्ता और पैरों में एक से डेढ़ फीट तक भरा गंदा पानी... यह दृश्य किसी बाढ़ग्रस्त इलाके का नहीं, बल्कि बदनावर क्षेत्र के ग्राम कड़ोदकलां का है, जहां पिछले 10 से 12 दिनों से कानवन-मांगोद मुख्य मार्ग पर जलभराव के कारण प्रतिदिन करीब 1500 से अधिक स्कूली विद्यार्थी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं।

यही रास्ता मस्जिद और बस्ती तक भी जाता है, जिससे आमजन और नमाजियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से चली आ रही इस समस्या पर पंचायत और संबंधित विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे अब आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

एक से डेढ़ फीट तक पानी भर जाता है

इसी मुख्य मार्ग पर तीन विद्यालय स्थित है। इनमें शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल के करीब 530, एक निजी विद्यालय के 640 तथा दूसरे निजी विद्यालय के 420 विद्यार्थी प्रतिदिन इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। बरसात होने पर पानी निकासी की समुचित प्रबंध नहीं किए जाने से सड़क पर एक से डेढ़ फीट तक पानी भर जाता है, जिससे बच्चों को जूते-चप्पल हाथ में लेकर पानी से होकर निकलना पड़ता है। कई बार तेज रफ्तार वाहनों के गुजरने से गंदा पानी बच्चों की ड्रेस, बस्तों और राहगीरों पर उछल जाता है।

ग्रामीणों का कहना है कि कानवन से मांगोद तक की सड़क का निर्माण वर्ष 2017 में हुआ था, लेकिन जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बरसात में यही स्थिति बन जाती है। इसके बावजूद न पंचायत और न ही संबंधित विभाग ने समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया। पंचायत को कई मर्तबा अवगत कराया गया लेकिन उनका रवैया उदासीन ही रहा। हाल ही में हुई वर्षा के दौरान नवीन कामदार के घर में भी पानी घुस गया था।

संक्रमण और हादसों का बढ़ा खतरा

सड़क पर कई दिनों तक गंदा पानी जमा रहने से डेंगू, मलेरिया और त्वचा रोग जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कीचड़ और फिसलन के कारण बच्चों के गिरकर घायल होने की आशंका बनी रहती है। कई अभिभावक ऐसे दिनों में बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतराते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

मदरसे के बच्चे भी नहीं पहुंच पा रहे

मार्ग के समीप स्थित मस्जिद में नमाज के लिए आने-जाने वालों को भी जलभराव के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। सदर मुबारिक खान ने बताया कि पानी निकासी नहीं होने से विशेषकर शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को काफी दिक्कत होती है। गंदे पानी से होकर गुजरना मजबूरी बन गया है। उन्होंने बताया कि मदरसे के करीब 40 बच्चे पिछले चार दिनों से नहीं पहुंच पाए हैं, जिससे उनकी तालीम भी प्रभावित हो रही है।

ग्रामीणों में बढ़ रहा आक्रोश

सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश रघुवंशी ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार पंचायत और संबंधित विभाग को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यदि जल्द जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो ग्रामीण सड़क जाम कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

जल्द समाधान करेंगे

पंचायत सचिव पूनालाल चौहान ने बताया कि सड़क निर्माण से जुड़े विभाग के अधिकारियों से बात की गई है। ग्रामीणों की शिकायत मिलने के बाद पानी निकासी की व्यवस्था कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा। वहीं लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एसडीओ राहुलसिंह गडरिया ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी मिली है। वे स्वयं मौके का निरीक्षण करेंगे और स्थिति का आकलन करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय

बारह साला बच्ची पर हैवानियत का कहर

अब आए दिन देश के प्रिंट मीडिया से लेकर अन्य सूचना माध्यमों में यौन अपराधों की विचलित करने वाली घटनाएं सुर्खियों में रहती हैं। यौन लिप्साओं का यह विस्फोट विचलित करने वाला है। कोई निर्भया, किसी के साहस के बूते अपने साथ हुए अन्याय को उजागर कर देती है, वहीं देश की अनेक निर्भयाएं यौन हिंसा व क्रूरता के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में त्रास झेलने को अभिशप्त हो जाती हैं। हाल की दो घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारह वर्षीय बालिका को चार दिन बंधक बनाकर दो दर्जन लोगों द्वारा दुराचार किया गया। इस मामले में 18 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ गिरफ्तारियां बाकी हैं। दूसरी घटना पश्चिम बंगाल की है जहां बारुईपुर में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। शव परीक्षण में पाया गया कि उसके सिर व निजी अंगों पर गंभीर चोटें थी। इतना ही नहीं, दुराचार के बाद उसे बोरे मे बंद करके जिंदा ही तालाब में डुबो दिया गया। दोनों ही घटनाएं विचलित करने वाली हैं, लेकिन श्रीगंगानगर की घटना हर संवेदनशील इंसान को हिला देने वाली है। जनाक्रोश के चलते प्रशासन ने न केवल 18 लोगों को गिरफ्तार किया बल्कि उन होटलों को भी ध्वस्त किया गया जहां अलग-अलग जगहों में बच्ची को बंधक बनाकर देह व्यापार कराया गया। निस्संदेह, मोबाइल के बढ़ते हस्तक्षेप से परिवार संस्था की चूलें हिली नजर आती हैं। कथित सोशल मीडिया समाज में विद्रूपताओं को जन्म दे रहा है। श्रीगंगानगर की बारह वर्षीय लड़की शहर से सौ किमी दूर अपने एक इंस्टाग्राम फ्रेंड से मिलने जाती है, जो उससे वहां दुराचार करता है। वहां से देर रात शहर लौटने पर एक रिक्शेवाले के झांसे में आकर होटल पहुंचती है और फिर उसके साथ दुराचार का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। परिजनों के लापता किशोरी के तलाश में थाने पहुंचने के बाद पुलिस हरकत में आती हैं, फिर उसे मुक्त कराया जाता है।

निरूसंदेह, ये घटनाएं इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। इस राक्षसी कृत्य से उद्वेलित लोग श्रीगंगानगर की सड़कों पर उतर आए। क्षुब्ध लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर कानून के रखवालों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जनाक्रोश को देखते हुए 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह कि भारतीय समाज में हो रहे यौन लिप्साओं के विस्फोट की वजह क्या है? ये नैतिक पतन की पराकाष्ठा क्यों हो रही है? ह्वस के भूखे भेड़िए न उम्र देखते हैं, न किसी बेटी की बेबसी। उस किशोरी के साथ हुई बर्बरता के बारे में सोचकर भी रूह कांपती है। जो शायद ही जीवनभर इस त्रासदी से उबर पाये। कहीं न कहीं इंटरनेट व सोशल मीडिया पर यौन स्वच्छंदता की पश्चिम की आंधी हमारे समाज को पतित कर रही है। हमारे परंपरागत शुचिता के रिश्तों को तार-तार करके निरंकुश यौन व्यवहार को तार्किक बताने की साजिश रची जा रही है। हम बच्चों को रामराज के संस्कार देते हैं, जबकि समाज में दानवराज का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। बच्चों को भी त्याग-तपस्या से लालन-पालन करने वाले मां-बाप की बजाय आभासी दुनिया के छद्म मित्र रास आ रहे हैं। जिसके सम्मोहन में यह किशोरी घर से निकली और उसका पहला शिकार बनी। ह्वस के भेड़िये भी परिस्थितियों की मारी लड़कियों को ही अपने शिकंजे में लेते हैं। ऐसे में बेटियों को भी घर से निकलते वक्त समय की संवेदनशीलता और लोगों की विश्वसनीयता को परखना चाहिए। घर वालों से चोरी-छिपे अनजान लोगों पर यकीन करने की वजह से अकसर बेटियां अपराधियों की आसान शिकार बनती हैं। यौन अपराधों के उफान के दौर में पुलिस और स्त्री रक्षा से जुड़ी एजेंसियों को भी नये दौर की नई चुनौतियों के मुताबिक तैयार करना होगा। इसमें चाइल्ड वेलफेयर से जुड़ी संस्थाओं की सजगता -सक्रियता बढ़ाने तथा पॉक्सो व जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को सख्त बनाने की जरूरत है। अभिभावक व स्कूल-कालेज बच्चियों को यौन-हिंसा से बचने और आत्मरक्षा से जुड़े विषयों पर गंभीर चर्चा करें। यदि इस दिशा में गंभीर पहल नहीं हुई तो पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर लगाए जा रहे 'रेप कैपिटल' के आरोप हकीकत समझे जाने लगेंगे।

अटलांटिक के ठंडे पानी से मानसून में बदलाव

मॉनसून हमारी जीवन रेखा है। भारत और दक्षिण एशिया के दूसरे हिस्सों में 1 अरब से अधिक लोग खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए मॉनसून पर निर्भर हैं। हर साल हम एक अच्छे मॉनसून की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय मॉनसून के पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है। वैज्ञानिक इस बदलाव के कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक नई रिसर्च से पता चलता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पानी के एक ठंडे हिस्से ने जेट स्ट्रीम हवाओं के जरिए भारतीय गर्मियों के मॉनसून में बदलाव शुरू कर दिए हैं। इससे करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी को खतरा पैदा हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दोनों प्रणालियों के बीच का संबंध एक ऐसे पहले से अज्ञात संबंध को दिखाता है जो दक्षिण एशिया में मौसम के अनुमानों को जानकारी दे सकता है और दूसरी जगहों पर मौसम की घटनाओं पर रोशनी डाल सकता है।

ध्यान रहे कि जेट स्ट्रीम हवाएं पृथ्वी के वायुमंडल में 9 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली तेज गति वाली, संकरी वायुधाराएं हैं। तापमान के अंतर और पृथ्वी के घूर्णन से संचालित ये हवाएं वायुमंडलीय सीमाओं के रूप में कार्य करती हैं जो वैश्विक मौसम के पैटर्न को आकार देती हैं और वाणिज्यिक विमानन मार्गों को प्रभावित करती हैं।

भारतीय गर्मियों का मॉनसून वर्षा का एक पैटर्न है जो जून से सितंबर तक रहता है और यह गर्म उत्तरी हिंद महासागर और भूमध्य रेखा के नीचे ठंडे समुद्री पानी के बीच तापमान के अंतर से चलता है। शुरू में, मॉनसून ने भारत के पश्चिमी तट और उत्तरी भारत के एक बड़े इलाके (गंगा के मैदान) में भारी बारिश शुरू की थी। लेकिन 1999 से यह पैटर्न बहुत बदल गया है। शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में पाया कि उत्तर-पश्चिम भारत में अब मॉनसून सीजन में 1999 से पहले के मुकाबले लगभग 25 प्रतिशत ज्यादा बारिश होती है, जबकि गंगा के मैदानी इलाकों में लगभग 4 प्रतिशत कम बारिश होती है।

इस अध्ययन के पहले लेखक और भारतीय विज्ञान संस्थान के जलवायु वैज्ञानिक महेंद्र निम्माकांति ने कहा कि यह परिवर्तन किसानों के लिए खास तौर पर बहुत बुरा है, क्योंकि उनके खेतों की मिट्टी और फसलें बारिश के पुराने पैटर्न के हिसाब से ढल गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत काफी हद तक खेती पर निर्भर है। उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक बारिश होने पर अचानक बाढ़ आ जाती है और फसलों का नुकसान होता है, क्योंकि इस इलाके की खेती सूखे हालात के हिसाब से ढल गई है। इस बीच, गंगा के मैदानी इलाकों में सूखे के दौर भी आए हैं, जिससे फसलों में भी कमी आई है और किसानों की रोजी-रोटी पर असर पड़ा है।

पिछले अध्ययनों ने भारतीय मॉनसून में परिवर्तन को अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (एएमओसी) में बदलाव से जोड़ा था। एएमओसी अटलांटिक में समुद्री धाराओं का एक बड़ा जाल है जो वैश्विक जलवायु को नियमित करता है और उत्तरी गोलार्द्ध में गर्मी पहुंचाता है। आंकड़े बताते है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से एएमओसी धीमा हो रहा है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में पहले के मुकाबले कम गर्मी छोड़ रहा है। निम्माकांति ने कहा कि इन अध्ययनों में यह नहीं बताया गया कि भारतीय मॉनसून कैसे बदल सकता है। इसके पीछे के तंत्र को भी विस्तार से नहीं समझाया गया। उन्होंने कहा, ये अध्ययन आम तौर पर यह समझाते हैं कि अगर एएमओसी कमजोर होता है, तो यह भारतीय मॉनसून को भी कमजोर करता है।

एक बड़ी समस्या यह है कि मौजूदा जलवायु मॉडल भारतीय मॉनसून में हुए बदलावों को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वे उत्तरी अटलांटिक महासागर की सतह के तापमान में बदलाव को भी पूरी तरह से ग्रहण नहीं करते हैं। इन मॉडलों ने ग्रीनलैंड के दक्षिण-पूर्व में एक अत्यंत ठंडे क्षेत्र पर गौर नहीं किया जिसे 'कोल्ड ब्लॉब' के नाम से जाना जाता है, जहां 1901 और 2021 के बीच पानी 1800 के दशक के आखिर की तुलना में ज्यादा ठंडा था। कोल्ड ब्लॉब बताता है कि एएमओसी कमजोर हो रहा है क्योंकि यह उत्तरी अटलांटिक तक पहुंचने वाली गर्मी की मात्रा में कमी की ओर इशारा करता है।

यह पता लगाने के लिए कि भारतीय मानसून कैसे और क्यों बदला है, शोधकर्ताओं ने दर्जनों जलवायु मॉडलों में बारिश का डेटा, समुद्र की सतह के तापमान के रिकॉर्ड और असल जिंदगी के दूसरे अवलोकन डाले। इसने पिछले 27 सालों में देखे गए बदलावों को फिर से दिखाया। इन नतीजों से उत्तरी अटलांटिक में हुए बदलावों और मानसून में बदलावों के बीच संबंध का पता चला। यह जानने के लिए क्या उत्तरी अटलांटिक समुद्र की सतह के तापमान की वजह से भारतीय मानसून अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है, टीम ने एक सिमुलेशन (कंप्यूटर पर परिस्थितियों की नकल) में कोल्ड ब्लॉब को जोड़ा और हटाया।

नतीजों से पता चला कि ठंडे ब्लॉब ने उत्तरी अटलांटिक पर एक मजबूत टेम्परेचर ग्रेडिएंट (तापमान में परिवर्तन की दर और दिशा का पैमाना) बनाकर भारतीय मानसून को शिफ्ट कर दिया है, जो बदले में यूरेशिया के ऊपर वायुमंडल में जेट स्ट्रीम हवाओं और प्रेशर सिस्टम पर असर डालता है। खासकर, उत्तरी अटलांटिक के ऊपर जेट स्ट्रीम तेज हो गई है, और पश्चिमी रूस में यूराल पहाड़ों के ऊपर एक 'ब्लॉकिंग' सिस्टम मजबूत हो गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत में मौसम सिस्टम बदल गए हैं, जो नमी वाली हवा को देश के उत्तर-पश्चिम की ओर ले जा रहे हैं और उसे दूसरे इलाकों से दूर खींच रहे हैं।

मुकुल व्यास

एजीयू एडवांसेज जर्नल में छपे नए नतीजों से मौसम का अनुमान लगाने वालों को भारत और पड़ोसी देशों में मॉनसून के दौरान बहुत ज्यादा बारिश और सूखे जैसी घटनाओं का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना ??है कि भारतीय मॉनसून वैश्विक जलवायु में एक निर्णायक बिंदु (टिपिंग प्वाइंट) है, और इन निष्कर्षों से पता चलता है कि यह सिस्टम 1999 में एक अहम सीमा पार कर गया था। तब से कोल्ड ब्लॉब की वजह से जेट स्ट्रीम में लगातार बदलाव हुआ है, जिससे मॉनसून में अचानक बदलाव आए हैं। अभी यह साफ नहीं है कि तेजी से बदलती जलवायु में भारतीय मॉनसून कैसे बदलेगा, क्योंकि जलवायु मॉडल उत्तर अटलांटिक के बारे में अलग-अलग अनुमान लगाते हैं, और दुनिया के बदलने के साथ-साथ दूसरे कारण भी असर डाल सकते हैं।

महसूस होने वाला तापमान बने गर्मी का पैमाना

मानसून के आगमन से पहले के दिनों में कदम बाहर निकालते ही हवा दमघोंटू महसूस होने लगती है। हवा सिर्फ गर्म नहीं हैय इसमें एक ऐसा भारीपन, सघनता और ठहराव है मानो वायुमंडल का वजन बढ़ गया हो और हमारी त्वचा को दबा रहा हो। दोपहर होते-होते, सामान्य वेदर ऐप हवा का तापमान 39 या 40 डिग्री सेल्सियस दिखा सकता है, जो देखने में शायद सहनीय लगे। लेकिन शरीर को यह तापमान 49-50 डिग्री सेल्सियस के समान महसूस होता है। यह कोई वहम नहींय 'हीट इंडेक्स' की वह डरावनी वास्तविक तस्वीर है जो साबित करती है कि हमारे पारंपरिक मौसम वैज्ञानिक पैमाने इंसानी शरीर के जलवायु संकट को मापने में बुनियादी रूप से विफल हो रहे हैं।

दशकों से, भारत में सार्वजनिक प्रशासन और आपातकालीन हीट प्रोटोकॉल केवल एक ही आंकड़े से संचालित हो रहे हैंरू एक साधारण थर्मामीटर पर आंका जाने वाला 'ड्राई-बल्ब' तापमान। यदि राजस्थान के सूखे मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री से. छू जाता है, तो उसे आधिकारिक तौर पर 'लू' (हीटवेव) घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मौजूदा उमस भरी गर्मी कहीं अधिक कपटपूर्ण थर्मोडायनामिक सिद्धांत पर काम कर रही है।

मानसून की देरी के कारण दक्षिण-पश्चिमी हवाएं आती हैं, तो ह्यूमिडिटी 60-70 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। मानव शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीने का वाष्पीकरण करता है। त्वचा से पसीना वाष्पीकृत होता है जो अपने साथ शरीर की आंतरिक ऊष्मा को बाहर ले जाता है। बहरहाल, जब आसपास की हवा पहले से ही नमी से पूरी तरह संतृप्त होकृएक भीगे हुए स्पंज की तरहकृतो वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया ठप हो जाती है। शरीर का आंतरिक अनुकूलन तंत्र काम करना बंद कर देता है, और उसका तापमान घातक सीमाओं की ओर बढ़ने लगता है। यह स्थिति हमें 'वेट-बल्ब तापमान' की चरम सीमा के खतरनाक रूप से करीब ले आती है जो कि मानव शरीर द्वारा झेली जा सकने वाली संयुक्त गर्मी और आर्द्रता की अंतिम सीमा है। अमेरिका के 'पेंसिल्वेनिया स्टेट हीट प्रोजेक्ट' के हालिया चिकित्सा अनुसंधान के मुताबिक, मानव शरीर मात्र 31 डिग्री सेल्सियस के वेट-बल्ब स्तर पर ही अपने आंतरिक तापमान पर नियंत्रण खोना शुरू कर देता है।

इस उमस भरे प्रहार का सबसे बड़ा खतरा है कि यह हमारी वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए संरचनात्मक रूप से अदृश्य बना रहता है। जून के अंत और अब जुलाई के शुरू में महानगरों में 'हीट इंडेक्स' 51 से 53 डिग्री पार कर गया। ड्राई-बल्ब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) कठोर नियामक मानदंडों के कारण अक्सर आधिकारिक तौर पर हीटवेव की घोषणा नहीं कर सका। इससे श्रमिकों की परेशानी की अनदेखी हुई। 'लू' घोषित नहीं होती, इसलिए श्रम प्रवर्तन एजेंसियां निर्माण श्रमिकों, डिलीवरी ब्वॉयज और कृषि मजदूरों के लिए दोपहर के विश्राम की अवधि निर्धारित नहीं करतीं। इन कामकाजी लोगों को 50 डिग्री की दहकती भट्ठी जैसी स्थिति में खटना पड़ता है। वहीं 'हीटस्ट्रोक' के मामलों में स्वास्थ्य प्रणालियां अक्सर उमस के दौर में हताहतों की संख्या कम आंकती हैं।

यदि भारत को ऐसे युग में जीवित रहना है जहां 'महसूस होने वाला' तापमान नियमित रूप से 50 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छू रहा हो, तो हमारी जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को क्रांतिकारी बदलाव से गुजरना होगा। आईएमडी और राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनियों, स्कूलों की छुट्टियों और श्रम नियमों के निर्धारण के कानूनी पैमाने के रूप में ड्राई-बल्ब थर्मामीटर को हटाकर आधिकारिक तौर पर 'कंपोजिट हीट रिस्क इंडेक्स' (संयुक्त ऊष्मा जोखिम सूचकांक) को लागू करना चाहिए। 65 फीसदी आर्द्रता वाले 40 डिग्री सेल्सियस के दिन को भी प्रशासनिक रूप से उतनी ही गंभीरता मिले, जितनी 47 डिग्री सेल्सियस वाले शुष्क दोपहर को।

इस दमघोंटू गर्मी के प्रति आम उपभोक्ताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया अधिक से अधिक निजी हाई-पावर सप्लिट एसी खरीदने की होती है। लाखों निजी एसी बेहद गर्म हवा सीधे तंग सड़कों पर छोड़ते हैं, जिससे 'अर्बन हीट आइलैंड' का प्रभाव गहरा हो जाता है। यह शहरी गरीबों के लिए सार्वजनिक रास्तों को 'थर्मल डेथ ट्रैप' बना देता है जो एसी नहीं खरीद सकते। भारत को इसके वैश्विक संरचनात्मक विकल्पों की ओर देखना चाहिए, जैसे फ्रांस का भूमिगत 'क्लाइमस्पेस' नेटवर्क या गुजरात के 'गिफ्ट सिटी' में हमारा अपना स्वदेशी मॉडल। हमें कूलिंग को एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक यूटिलिटी के रूप में अपनाना होगाकृयानी ऐसे 'डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम' जो इंसुलेटेड पाइपों के जरिए ठंडे पानी को पूरे वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में घुमाकर ठंडा रख सकें।

प्रो. पूर्णेन्दू रंजन

भवन नियमों को शीशे और कंक्रीट के उन ढांचों से दूर हटना होगा जो विशाल ग्रीनहाउस जाल की तरह काम करते हैं। 'ऊर्जा संरक्षण भवन कोड' लागू कर इमारतों में प्रकाश परावर्तित करने वाली ठंडी छतें, क्रॉस-वेंटिलेशन के रास्ते और खोखली इंसुलेटेड ईंटों का उपयोग अनिवार्य किया जाए। यह अंदरूनी तापमान को 5 डिग्री तक कम कर सकता है, जिससे रहने के लिए एसी पर निर्भरता कम हो जाएगी।

जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन को सीधे नहीं, बल्कि विभिन्न कारकों को आपस में मिलाकर तेजी से प्रभावित कर रहा है। जब हवा का तापमान कुछ और कहे और इंसान की त्वचा कुछ और महसूस करे, तो हमारी सार्वजनिक नीतियों को हमेशा इंसान की त्वचा का साथ देना होगा। यह समय साधारण थर्मामीटर को विदा करने और एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार करने का है जो हवा के इस भारी और वास्तविक संकट का दृढ़ता से मुकाबला कर सके।

पारिवारिक त्याग की अनदेखी कर आजादी की चाह

फरीदाबाद में राहुल नाम के लड़के ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने वीडियो बनाया और कहा कि वह घर के सारे काम करता है, व्यापार भी करता है, फिर भी उसकी पत्नी उसे मारती-पीटती है। दूसरा किस्सा पुणे के केतन का है, कहा गया कि उसकी मंगेतर सिया ने अपने मित्र चेतन की मदद से उसे लोहागढ़ पहाड़ी से धक्का दे दिया। सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी क्योंकि केतन के सिर पर बाल नहीं थे और वह हकलाता भी था। इन दोनों मामलों में युवाओं ने जान गंवाई। इनके घर वालों, परिजनों पर क्या गुजरी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। मगर अफसोस की बात ये है कि इन दोनों की मृत्यु को स्त्री अधिकारों के नाम पर सेलिब्रेट किया गया। कहा गया कि अब तक स्त्रियां सहती रही हैं, मगर अब वे बदला ले रही हैं।

मुस्कान सोनी नाम की दांतों की डॉक्टर ने तो बाकायदा केतन की मौत का मजाक उड़ाया कि उसके साथ तो ऐसा होना ही था और हा-हा-हा करते वीडियो पोस्ट किया। हालांकि बाद में इस डॉक्टर ने माफी भी मांगी।

जब हम अधिकारों की बात करते हैं, तो उनका अर्थ हमारे दैनंदिन जीवन की सुविधाओं से जुड़ा होता है। छोटे, बड़े की भावना को खत्म करने की बात होती है। लेकिन मृत्यु पर हंसना, मीम्स बनाना, कहना कि वक्त आ गया है कि अब स्त्रियों को अपने प्रति किए गए हर अपराध का बदला लेना चाहिए, कितना दुखद है। अंग्रेजी की एक बड़ी लेखिका और एक बड़े लेखक ने तो यह तक कहा कि सिया ने केतन को मारा, इसके लिए सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि हमारे परिवारों का ढांचा जिम्मेदार है। जहां लड़कियों को कुछ करने की आजादी नहीं। वे न अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, न देर रात लौट सकती हैं, न शराब पी सकती हैं। ऐसा कहने वाले वे लोग हैं, जो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले हैं। जिनके इर्द-गिर्द सेवकों और सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी फौज है, लेकिन ज्ञान वे उन आम लड़कियों को दे रहे हैं, जो अमूमन अपराध की जद में होती हैं। 'अपनी सुरक्षा अपने हाथ' वाली कहावत इन पर चरितार्थ होती है। फिर देर रात तक पार्टी करना या शराब पीना आम लड़कियों का जीवन नहीं है। और क्या स्त्रियों के लिए शराब पीना इतनी अच्छी बात है। फिर ऐसा क्यों है कि एक के घर वालों को दोष दे रहे हैं। पश्चिम का उदाहरण बार-बार दिया जा रहा है कि वहां देखो स्त्रियों को कितनी आजादी है। क्या सचमुच!

अक्सर महिलाएं अपने घर के आसपास शराब के ठेके खुलने का विरोध करती हैं। शराबबंदी की मांग करती हैं क्योंकि शराब के कारण ही उनके पति तरह-तरह की हिंसा करते हैं। यदि वे पैसे भी कमाएं, तो उनके पैसे शराब पीने के लिए छीन लिए जाते हैं। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है।

गांधी जी जिन्होंने कहा था कि शराब आत्मा का नाश करती है, उनकी इस शिक्षा को भी लोग भूल गए हैं। डाक्टरों की सलाह भी याद नहीं रखते, जो कहते हैं कि शराब पीने से शरीर के तमाम अंगों पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। यदि इन लोगों की मानें तो देश में चलने वाले जितने नशा मुक्ति केंद्र हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए।

लेकिन 'माई लाइफ और माई च्वाइस' का विचार एलीट स्त्री-पुरुषों के मन में इतना बसा हुआ है कि वे अपनी शर्तों को दूसरों पर लाद रहे हैं और इन्हें ही दूसरों की च्वाइस बता रहे हैं। वे सिया का बचाव करते हुए उसके घर वालों और हर अपने यहां माता-पिता बच्चों को हमेशा बच्चा मानते हुए, उनकी सुरक्षा की चिंता करते हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई का खर्चा उठाते हैं। पढ़ने के लिए विदेश भेजते है। करोड़ों रुपये का लोन लेते हैं, उसे खुद चुकाते हैं। बच्चों के लिए घर बनाते हैं। यानि कि अपनी उम्र और सारे संसाधन वे बच्चों के लिए लगा देते हैं, जिससे उनका जीवन आसान हो सके। माता-पिता के सारे संसाधन चाहिए, लेकिन जीवन अपनी शर्तों पर जीना है। कौन रोकता है, लेकिन फिर संसाधन भी खुद जुटाइए। माता-पिता की जमीन-जायदाद में भी हिस्सा मत मांगिए। बीमारी-हारी में भी अपनी मदद खुद कीजिए। ड्रीम वैडिंग करना हो, तो खुद पैसे जुटाइए। उनके सम्पर्कों का भी लाभ मत उठाइए।

अधिकार बिना कर्तव्यों के नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हां मन की बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं।

विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं चुकाते। विदेशों में कई ऐसे आदमियों से मिली, जिनकी उम्र पचास के पार है, लेकिन अभी तक वे अपनी पढ़ाई के लिए उठाए गए कर्ज को चुका रहे हैं। भारत में तो माता-पिता की हालत ये है कि ताउम्र खटते भी हैं और पिटते भी हैं। बातें बनाते रहिए कि बुजुर्गों के लिए क्या-क्या होना चाहिए।

विमर्शों की नकारात्मकता कितनी है कि जहां मौत का भी जश्न मनाया जाए। जाति, धर्म, लिंग देखकर शोक और खुशी प्रकट की जाए, इससे यही पता चलता है कि हमारा वैचारिक आधार कितना पोला है, जहां हम किसी मरने वाले की जाति या जेंडर देख रहे हैं। उसके राजनीतिक विचारों के आधार पर उसकी मौत की खुशी या दुःख मना रहे हैं। इसका पहली बार अहसास पत्रकार रोहित सरदाना की मौत पर हुआ। जब एक मशहूर इनफ्लुएंसर ने कहा कि यह अकेला क्यों मर गया, इसके बीवी -बच्चे क्यों नहीं मर गए। यह एक तरह से वही हिटलरी विचार है, जिसकी आलोचना करते-करते ऐसे लोग दुबले हुए जाते हैं। यदि बच्चों को अपनी पसंद से विवाह करने दिया जाए तो भी उनका जीवन सुचारु रूप से चलेगा, इसकी क्या गारंटी है। अपनी पसंद से शादी करने के बाद भी इन दिनों कितने मामले ऐसे आते हैं, जहां पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को और बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को।

क्षमा शर्मा

चर्चित घटना में भरत तिवारी की मौत के मामले में तो बहुत से नेता भी कूद पड़े और कहने लगे कि उसके वर्ग ने जो किया है, वह तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा।

कोई सवर्ण, कोई दलित, कोई स्त्री, कोई पुरुष, किसी की भी मृत्यु हंसने और आनंद मनाने के लिए कैसे हो सकती है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक से एक नफरती विचारों की होड़ लगी है। सोचते तो ये थे कि तकनीक बढ़ेगी, तो तमाम तरह के नफरत फैलाने वाले विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उलटा है। नफरत और बदले की भावना की फसल लहलहा रही है। लोग भूल रहे हैं कि नफरत से नफरत उपजती है और बदले से बदला।

तेज बारिश से सड़कों पर दो से तीन फीट तक पानी बह निकला

बिनोबा नगर में खुले नाले और तेज बहाव से खतरा

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में अब मानसून की सक्रियता से माहौल बदलता जा रहा है। रुक-रुककर कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश का दौर चल रहा है। मंगलवार सुबह के बाद शाम साढ़े चार बजे जोरदार गरज-चमक के साथ झमाझम का दौर शुरू हुआ। शहर में कई स्थानों पर जल निकासी नहीं होने से सड़कों पर दो से तीन फीट तक पानी बहने लगा।

मौसम साफ रहने के दौरान किसान परिवार के साथ खरीफ सीजन की सोयाबीन, मक्का, कपास आदि की बोवनी कर रहे हैं। सहायक संचालक कृषि भीका वास्के ने बताया कि जिले में अब तक 80 फीसद से अधिक बोवनी हो चुकी है। दो-चार दिन में शत-प्रतिशत बोवनी का लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

हालांकि जिला गत वर्ष की तुलना में काफी पीछे हैं। गत वर्ष अब तक जिले में औसत 336.88 मिमी वर्षा हुई थी।

सोमवार के मुकाबले मंगलवार को अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। सुबह की आर्द्रता 95 प्रतिशत व शाम की 94 प्रतिशत रही, जो सोमवार को क्रमशरू 90 व 73 प्रतिशत थी।

बिनोबा नगर में खुले नाले और तेज बहाव से खतरा

शहर के विनोबा नगरदूजवाहर नगर स्थित मुक्तिधाम मार्ग पर दो निजी स्कूल के समीप बना खुला नाला वर्षाकाल के दौरान गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। लगातार वर्षा से नाले में तेज बहाव होने के कारण पानी खुले हिस्से से गुजर रहा है। वर्षा के समय सड़क पर पानी भर जाने से यह पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि सड़क कहां समाप्त हो रही है और नाला कहां से शुरू हो रहा है।

इसी मार्ग से प्रतिदिन दोनों विद्यालयों के सैकड़ों छात्र-छात्राएं, उनके अभिभावक तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक आवागमन करते हैं। यह मार्ग रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी प्रमुख रास्तों में शामिल है। तेज बहाव और खुले नाले के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

केदारेश्वर में गिरने लगा झरना

सैलाना क्षेत्र में पिछले दो-तीन दिनों से हो रही वर्षा के बाद सैलाना-सरवन मार्ग स्थित केदारेश्वर महादेव मंदिर पर प्राकृतिक झरना गिरने लगा है। झरना शुरू होते ही मंदिर परिसर का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठा है।

चारों ओर फैली हरियाली ने इस रमणीय स्थल की छटा को और आकर्षक बना दिया है। वर्षा के साथ सक्रिय हुए इस झरने का आनंद लेने के लिए आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों के बड़ी संख्या में पहुंचने की संभावना है।

पानी के टैंक से एक साथ निकले 20 कोबरा

माही की गूंज, मंदसौर।

मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर की सस्यंक डायमंड कॉलोनी में, जहां स्थित एक मकान के पानी के टैंक से एक-दो नहीं बल्कि 20 कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि, ये सभी अभी बच्चे हैं, लेकिन सर्प विशेषज्ञों की मानें तो कोबरा एक ऐसा विषैला सांप है, जिसके बच्चे में व्यस्क के मुकाबले अधिक जहर होता है। ऐसे में स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। इधर, घटना की जानकारी सर्पमित्र कमलदास बैरागी को सूचना दी गई। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे बैरागी ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें वन क्षेत्र में छोड़ा गया है।

हक्का-बक्का रह गया परिवार

जानकारी के अनुसार, सम्यंक कॉलोनी में रहने वाले भेरूलाल के मकान में स्थित पानी के टैंक में कुछ दिनों से हलचल महसूस हो रही थी। कोई उन्हें सांप बताता तो कोई कुछ और ऐसे में मकान मालिक भेरूलाल ने सर्पमित्र कमल दास को इसकी सूचना दी। कमलदास मौके पर पहुंचे तो उन्होंने घर में बने पानी के टैंक की पड़ताल की तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने परिवार को बताया कि, पहली चीज तो टैंक के पानी में दिखने वाली चीजें सांप हैं और वो भी कोबरा। कमलदास के मुंह से कोबरा का नाम सुनते ही घर के सभी लोग हक्के-बक्के रह गए। वो इसपर खुशी जता रहे थे कि, उन्होंने संदिग्ध समझकर उन सांपों को खुद टैंक से निकालने का प्रयास नहीं किया। वरना वो नुकसान भी पहुंचा सकते थे।

वन्य क्षेत्र में छोड़े गए सभी कोबरा

सर्पमित्र कमल दास के सामने उन सभी कोबरा को टैंक से बाहर निकालना बड़ी चुनौती थी। टैंक के अंदर उतरकर कोबरा को बाहर निकालना बेहद मुश्किल था। यानी किसपर नजर बनाएं और किसे पकड़ें। एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। ऐसे में कमलदास ने पहले तो टैंक में टैंकर से पानी डलवाया, जिससे टैंक का जल स्तर बढ़ा। टैंक में 7 टैंकर पानी डलने के बाद वाटर लेवल ग्राउंड तक आया। इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से ग्लब्ज पहने और सावधानी पूर्वक सभी कोबरा को टैंक से बाहर निकाला। इस तरह पकड़े गए कोबरा के बच्चों की गिनती की गई तो वो 20 निकले। फिलहाल, सभी को सुरक्षित टैंक से रेस्क्यू कर शहरी इलाके से दूर वन्य क्षेत्र में छोड़ दिया गया है।

सोने-चांदी के कैश और बिल के भावों में फिर अंतर

माही की गूंज, रतलाम।

अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारी उथल-पुथल से थोड़े-थोड़े अंतराल में सोना-चांदी के भाव में लंबा उतार-चढ़ाव आ रहा है। इससे सराफा बाजार में कामकाज की की रफ्तार धीमी पड़ गई है। भावों में कभी तेज उछाल तो कभी अचानक गिरावट से निवेशकों के साथ-साथ कारोबारियों की चिंता भी बढ़ गई है। बाजार में अनिश्चितता का माहौल होने से खरीद-बिक्री के निर्णय प्रभावित हो रहे हैं और निवेशकों का रुझान भी धीरे-धीरे कम होता दिखाई दे रहा है।

सराफा कारोबारियों के अनुसार करीब एक सप्ताह पहले तक सोना और चांदी के हाजर (नकद) तथा बिल के भाव लगभग समान स्तर पर थे, लेकिन वर्तमान में दोनों के बीच फिर बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। चांदी का बिल भाव करीब 2.40 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि हाजर बाजार में यही चांदी लगभग 2.33 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।

कैश और बिल का अंतर बना कारोबारियों के लिए चुनौती

इसी तरह सोना बिल में करीब 1.49 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि हाजर बाजार में इसका भाव करीब 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। दोनों धातुओं में बिल और हाजर के बीच हजारों रुपये का अंतर कारोबारियों के लिए चुनौती बन गया है।

व्यवसायी प्रतीक जैन और ऋषभ संघवी का कहना है कि इस तरह की स्थिति में ग्राहकों को भाव समझाना भी कठिन हो रहा है। कई ग्राहक भावों में स्थिरता आने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ निवेशक बाजार में जोखिम बढ़ने के कारण फिलहाल निवेश से दूरी बना रहे हैं। इसका सीधा असर सराफा बाजार के दैनिक कारोबार पर दिखाई दे रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव डालर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम तथा निवेशकों की बदलती रणनीतियों का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा आयात लागत, कर व्यवस्था और स्थानीय मांग-आपूर्ति जैसे कारक भी बिल व हाजर भावों के बीच अंतर बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं।

सराफा बाजार में सतर्कता का माहौल

सराफा व्यापारियों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में कीमतों में स्थिरता नहीं आती है तो बाजार की सामान्य गतिविधियां और अधिक प्रभावित हो सकती हैं। फिलहाल अधिकांश कारोबारी सीमित स्टाक के साथ काम कर रहे हैं और बड़ी खरीदारी से बच रहे हैं।

वहीं निवेशक भी बाजार की दिशा स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सराफा बाजार में फिलहाल सतर्कता का माहौल बना हुआ है और सभी की नजर आगामी दिनों में सोना-चांदी के भावों की चाल पर टिकी हुई है।

एक नजर सोना-चांदी के भाव पर

(नोट : आरटीजीएस भाव चांदी प्रति किलो व सोना प्रति 10 ग्राम रुपये में)

तारीख	चांदी	सोना	तारीख	चांदी	सोना
06 जुलाई	240100	149200	27 जून	228100	147200
04 जुलाई	240100	150000	26 जून	227800	145700
03 जुलाई	240100	150500	25 जून	223600	143900
02 जुलाई	231100	147000	24 जून	228400	143800
01 जुलाई	227100	144000	23 जून	233100	148600
30 जून	230100	145200	22 जून	242100	151000
29 जून	225100	145000	20 जून	238100	149300

ग्रीन फील्ड फोरलेन का भूमिपूजन फिर टला

माही की गूंज, रतलाम।

केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 9 जुलाई 2026 को सुबह मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाले जावरा आने वाले थे, लेकिन 8 जुलाई को नया अपडेट सामने आया है कि, नितिन गडकरी का दौरा अंतिम समय में निरस्त हो गया है। संभवतरू प्रदेश के साथ साथ जिलेभर के खराब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि, गडकरी जावरा से जावरा-उज्जैन ग्रीन फील्ड फोरलेन निर्माण के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। लेकिन, अब गडकरी का दौरा टलने से एक बार फिर भूमिपूजन कार्यक्रम भी टल गया है।

खास बात ये है कि, गडकरी का ये दौरा बुधवार सुबह अचानक ही तय किया गया था। संभावित प्रोग्राम को लेकर अपडेट सामने आते ही पूरे जिले में प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ गया था। जावरा के पास अरनिया पिथा कृषि उपज मंडी प्रांगण में कार्यक्रम आयोजन करने की तैयारी शुरू की जा चुकी थी। किसानों ने जो माल डोम में रखा था, उसे हटाकर साइट में रखवाया जाने लगा था। वहीं, गडकरी और सीएम का कार्यक्रम के चलते 9 जुलाई को मंडी का अवकाश घोषित किए जाने की भी संभावनाएं लगाई जाने लगी थीं। हालांकि, जिला प्रशासन की ओर से उसपर फैसला नहीं लिया गया था।

तैयारियों में जुट गया था प्रशासन

बुधवार सुबह गडकरी के दौरे से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद एसडीएम, एसडीओपी सीएसपी समेत पूरा जिला प्रशासन मंडी प्रांगण में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया था। हालांकि, केंद्रीय मंत्री गडकरी के जावरा रुकने और ग्रीनफील्ड फोरलेन का भूमिपूजन करने संबंधित अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं हुआ था। फिर भी शासन स्तर से मिले इनपुट के बाद प्रशासन तैयारियां करने लगा था। इसी बीच प्रशासन को अधिकृत जानकारी मिली है कि, कार्यक्रम निरस्त किया गया है।

मंडी के प्लेटफार्म और डोम को किया जा रहा था तैयार

इसके पहले मंडी में प्लेटफार्म और डोम का उपयोग कार्यक्रम में कैसे हो सकता है, उसकी तैयारी भी करनी शुरु कर दी गईं थीं। क्योंकि, बारिश के बीच इतने कम समय में नया डोम बनाना तो संभव नहीं था। इसलिए वहां बने किसानों के उपज रखने वाले डोम और प्लेटफार्म पर कार्यक्रम की तैयारी शुरु कर दी गई थीं। फिलहाल, अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि, कल होने वाला नितिन गडकरी का दौरा फाइनली निरस्त हो गया है। अब देखना होगा कि, लंबे समय से अटके जावरा-उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे का काम के लिए भूमिपूजन की अगली तारीख क्या तय होती है।

फौजी कश्मीर में कर रहा ड्यूटी, परिवार अपनी जमीन पर नहीं कर पा रहा बोवनी

माही की गूंज, मंदसौर।

ग्राम नैनोरा के मोहनलाल रेगर भारतीय सेना में हैं। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में तैनात हैं। यहां गांव में उनकी पत्नी व बच्चे अपनी ही जमीन पर बोवनी के लिये परेशान हो रहे हैं। फौजी एवं उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोग बेवजह विवाद कर रहे हैं, जबकि खेत उनका हैं, न्यायालय से केस भी जीत चुके हैं, पुलिस अधिकारियों के सामने राजीनामा भी हुआ था, बावजूद खेत पर बोवनी नहीं करने दी जा रही हैं, जबकि पूरे गांव में सभी किसानों के खेतों में बोवनी हो चुकी हैं।

अपने ही खेत पर बोवनी के लिये परेशान हो रहे फौजी मोहनलाल रेगर की पत्नी द्वारा 16 जून को जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन सौंपकर बोवनी के लिये पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। फौजी मोहनलाल रेगर ने बताया की अब तक पुलिस सुरक्षा नहीं मिली हैं। गांव के ही जो लोग बेवजह विवाद करते हैं और हमें हमारी जमीन पर बोवनी नहीं करने देते हैं उनसे हमारा कोई विवाद नहीं हैं फिर भी मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा हैं।

16 जून पुलिस अधीक्षक को जनसुनवाई में सौंपे आवेदन में फौजी मोहनलाल रेगर की पत्नी निर्मलाबाई ने बताया था की मेरे पति भारतीय सेना फौज में देश की सेवा में तैनात हैं और अक्सर ड्यूटी पर बाहर रहते हैं। पति के बाहर होने के कारण मैं गांव में अपने बच्चों और परिवार के साथ अकेली रहती हूं तथा खेती व मजदूरी कर जीवन यापन करती हूं। ग्राम नेनौरा में मेरे नाम पर कृषि भूमि स्थित हैं, जिसका खसरा नंबर 49ध्4 बराबर 50, 54ध्1 बराबर 60, 57ध्2ध्2 बराबर 13 हैं। इसका कुल रकबा 123 आरी (पांच बीघा) तथा 6 आरी अतिक्रमण की जमीन हैं।

इस भूमि पर मैं पिछले 25 वर्षों से मालिकाना हक के साथ स्वयं खेती करती आ रही हूं। उक्त भूमि की रजिस्ट्री पावती व नामांतरण मेरे नाम पर दर्ज हैं। नारायणगढ़ कोर्ट से केस जीतकर मुझे इसका कानूनी कब्जा मिला हैं। पुलिस, प्रशासन, गिरदावर, आरआई, नायाब नाजिर और पटवारी द्वारा बकायदा सीमांकन (नपती) कर जेसीबी से खाई भी खुदवाई गई थी, जो प्रशासनिक रिकार्ड में दर्ज हैं। 18 नवंबर 2025 को एसडीओपी व टीआई सा. की उपस्थिति में राजीनामा भी हुआ था। उसके बावजूद गांव के ही कुछ लोग बेवजह हमने विवाद कर रहे हैं, रास्ता रोकते हैं। इनकी वजह से अब तक खेत में बोवनी नहीं कर पा रहे हैं। मांग की गई थी की बोवनी के लिये पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाये। लेकिन अब तक पुलिस सुरक्षा नहीं मिली हैं। अब तक फौजी का परिवार अपने खेत में बोवनी नहीं कर पाया हैं।

आवारा कुत्ते ने ऐसा दौड़ाया कि कुएं में गिरे 13 हिरण

माही की गूंज, शाजापुर।

शुजालपुर अनुभाग की कालापीपल तहसील के खरदौनकलां में सुबह हृदयविदारक घटना सामने आई। गांव से लगे एक खेत के कुएं में 13 हिरणों और एक कुत्ते के शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की तथा सभी वन्यजीवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार कराया।

बताया जा रहा है कि खेत के मालिक फसल पर कीटनाशक छिड़काव करने पहुंचे थे। इसी दौरान नजर खेत स्थित कुएं में पड़ी, जहां बड़ी संख्या में हिरण मृत दिखे। उन्होंने तत्काल सरपंच को सूचना दी। इसके बाद पुलिस के माध्यम से वन विभाग को अवगत कराया।

एक साथ कुएं में गिरे 13 हिरन

प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि हिरणों का समूह किसी आवारा श्वान से बचने के लिए तेज गति से भाग रहा था। इसी दौरान अंधाधुंध दौड़ते हुए सभी कुएं में गिर गए। जिस कुत्ते से वे बचने का प्रयास कर रहे थे, वह भी कुएं में गिर गया और उसकी भी मौत हो गई। मृत हिरणों में चार नर एवं नौ मादा हैं। ग्रामीणों के अनुसार कुएं पर सुरक्षा के लिए मुंडेर बनी हुई है, लेकिन एक हिस्सा क्षतिग्रस्त मिला। आशंका है इसी स्थान से हिरण कुएं में गिरे।

घटना कब हुई, इसका स्पष्ट पता नहीं चल सका। हालांकि जब खेत मालिक रविवार को पहुंचे तो तेज दुर्गंध आ रही थी। नीचे देखने पर हिरणों और श्वान के शव सड़-गल चुके थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत एक-दो दिन पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने तत्काल सरपंच को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग मौके पर पहुंचा।

मृत वन्यजीवों का हुआ अंतिम संस्कार

सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी, नायब तहसीलदार तथा विभागीय अमला मौके पर पहुंचा। वन्यजीव संरक्षण के नियमों के तहत पंचनामा तैयार किया गया, शवों का परीक्षण करवाते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई। वन्य अमले ने ग्रामीणों के सहयोग से मृत वन्यजीवों का अंतिम संस्कार किया।

शुजालपुर-कालापीपल क्षेत्र हिरणों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। खेतों और खुले इलाकों में अक्सर हिरणों के झुंड देखे जाते हैं। हिरणों की बढ़ती संख्या एवं किसानों की परेशानी को देखते हुए पूर्व में विशेष अभियान चलाक हेलिकॉप्टर की मदद से बड़ी संख्या में हिरणों को पकड़कर प्रदेश के विभिन्न अभयारण्यों में स्थानांतरित किया जा चुका है। बावजूद क्षेत्र में आज भी बड़ी संख्या में वन्यजीव विचरण करते हैं।

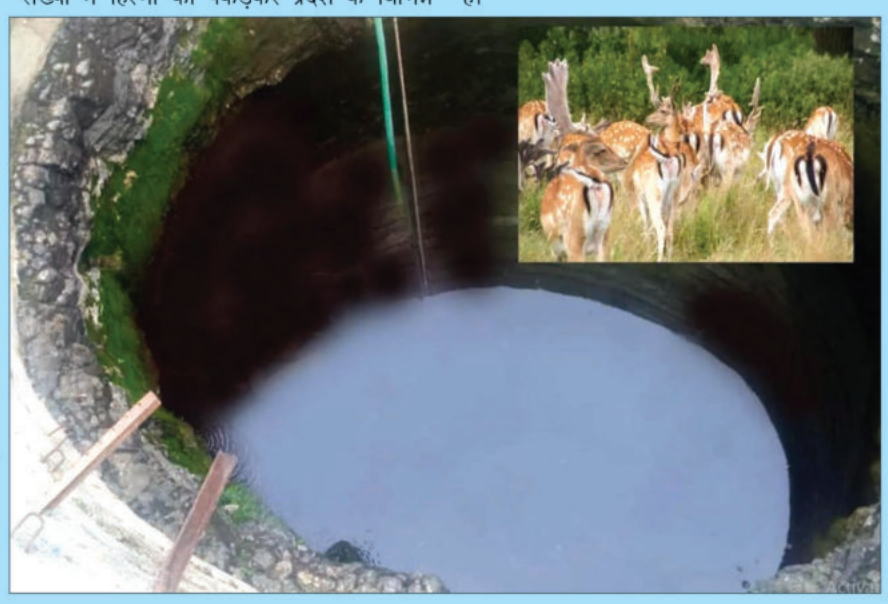

प्रोटोकॉल दर्शन के नाम पर अवैध वसूली, सुरक्षा गार्ड व फोटोग्राफर जेल भेजे गए

माही की गूंज, ओंकारेश्वर।

ज्योतिर्लिंग के दर्शन को लेकर प्रोटोकॉल व्यवस्था एक बार फिर विवादों में आ गई है। प्रोटोकॉल दर्शन के नाम पर 11 श्रद्धालुओं से 13 हजार 200 रुपए की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। घटना के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने व्यवस्था की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पुनासा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंकज वर्मा ने मंगलवार को बताया कि मामले में मंदिर के एक सुरक्षा गार्ड और एक स्थानीय छायाकार को जेल भेज दिया गया है।

पुलिस विभाग ने भी ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर दो पुलिसकर्मियों अमन और धर्मेंद्र को लाइन अटैच किया है। इसके अलावा मंदिर में तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों का चरित्र सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। पंकज वर्मा ने कहा कि श्रद्धालुओं के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा भविष्य में भी ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत के अनुसार श्रद्धालुओं से प्रोटोकॉल दर्शन के नाम पर राशि वसूली गई थी। हालांकि बाद में कुछ श्रद्धालुओं ने ओंकारेश्वर से बाहर जाकर ठगी होने से इनकार कर दिया। इससे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। यदि ठगी नहीं हुई थी तो शिकायत क्यों की गई और यदि शिकायत सही थी तो बाद में बयान क्यों बदले गए।

प्रशासन का कहना है कि प्रोटोकॉल दर्शन की सुविधा सामान्य श्रद्धालुओं के लिए नहीं होती। संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुशंसा पर ही अधिकृत सूची प्रोटोकॉल समूह में भेजी जाती है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि आम लोगों तक प्रोटोकॉल से जुड़ी जानकारी या लिंक कैसे पहुंचा। मामले में किसी स्तर पर मिलीभगत रही है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है।

पूर्व में भी कई जनप्रतिनिधि प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था को समाप्त करने अथवा इसे अधिक पारदर्शी बनाने की मांग कर चुके हैं। यह मामला केवल 13 हजार 200 रुपए की वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है जिस पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं का विश्वास टिका हुआ है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने कार्रवाई करते हुए सभी सुरक्षाकर्मियों को दो दिवस के भीतर चरित्र सत्यापन कर प्रमाण-पत्र जमा करने के निर्देश दिए हैं।

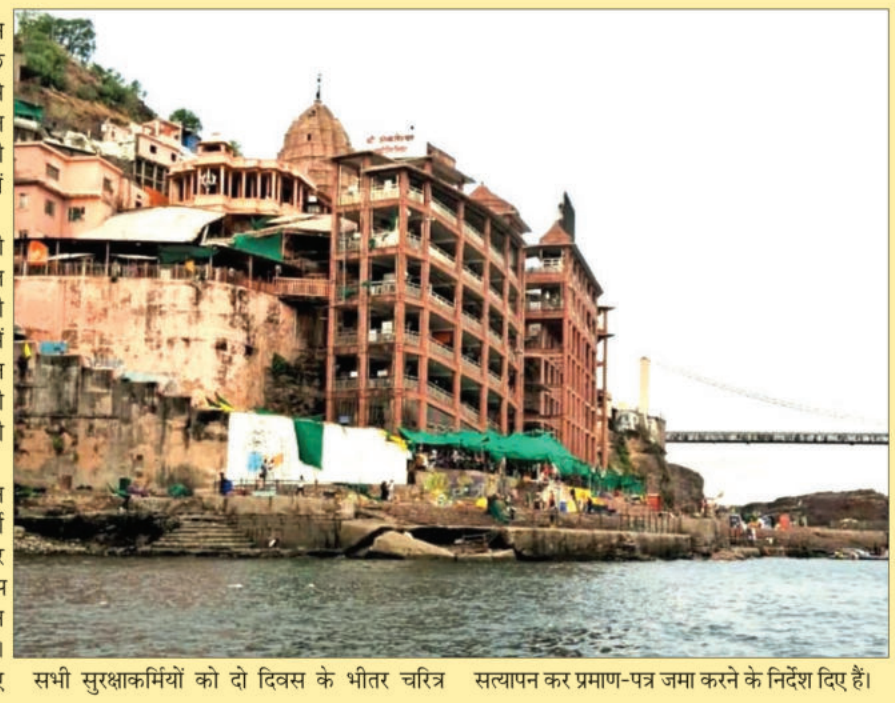

बायपास पर यात्री बस और पिकअप की टक्कर, एक की मौत

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले के कुक्षी बायपास मार्ग पर मंगलवार दोपहर एक यात्री बस और महिंद्रा पिकअप वाहन की आमने-सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार दो महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा।

कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि दोपहर करीब साढ़े बारह बजे इंदौर से बड़वानी आ रही यात्री बस, जिसमें लगभग 25 यात्री सवार थे, सामने से आ रही महिंद्रा पिकअप से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शी विनय यदुवंशी के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। टक्कर के बाद पिकअप वाहन सड़क पर पलट गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई।

अस्पताल पुलिस चौकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना में पिकअप चालक राहुल चंद्रकांत सिरसाठ (31), निवासी नासिक (महाराष्ट्र) की मृत्यु हो गई। वहीं बस में सवार कविता चौहान बेगलिया (21) और दुर्गेश्वरी राठौर (29), दोनों निवासी अंजड़, घायल हो गईं।

सूचना मिलते ही पुलिस और तहसील प्रशासन की टीम एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंची तथा घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

दुर्घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने बायपास और मुख्य मार्गों पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे वाहनों को लेकर चिंता जताई। लोगों का कहना है कि यात्री बसों के साथ कई स्कूल बस चालक भी निर्धारित गति सीमा का पालन नहीं करते, जिससे विद्यार्थियों और राहगीरों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से स्कूल बसों की नियमित जांच कराने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

2 लाख लेकर बेटी नहीं भेजी तो किया अपहरण

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले की राजपुर तहसील क्षेत्र से एक युवती को दिनदहाड़े खेत से जबरन ले जाने का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि युवती के परिजनों ने बेजा प्रथा के तहत करीब दो लाख रुपए लेने के बाद भी बेटी को नहीं भेजा। इसके बाद 25 से 30 युवक गांव पहुंचे और युवती को खेत से पकड़कर मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गए। घटना का वीडियो 7 जुलाई की दोपहर का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य प्रतिनिधि राहुल सोलंकी ने कहा कि यदि वीडियो में दिखाई दे रही घटना सही है तो यह कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। उन्होंने पुलिस से 24 घंटे के भीतर मामले की जांच कर तथ्य सार्वजनिक करने की मांग की है।

राजपुर थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर ने बताया कि मामले में अब तक कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि जांच के लिए पुलिस दल को गांव भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार युवती का रिश्ता निहाली गांव निवासी हुकुम रावत से तय हुआ था। बेजा प्रथा के अनुसार हुकुम की ओर से युवती के परिजनों को दो लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन लड़की पक्ष उसे हुकुम के घर नहीं भेज रहा था। इसके बाद हुकुम 25 से 30 लोगों के साथ इंद्रपुर गांव पहुंचा और खेत में मौजूद युवती को जबरन अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया।

वीडियो में भी कुछ लोग आपस में बातचीत करते सुनाई दे रहे हैं कि युवती का बेजा हो चुका है, लेकिन उसके परिजन रुपए लेने के बावजूद उसे नहीं भेज रहे थे, जिसके बाद उसे जबरन ले जाया गया।

ग्रामीणों के अनुसार हुकुम का युवती से रिश्ता तय हुआ था और दोनों कुछ समय तक साथ भी रहे। बाद में युवती को पता चला कि हुकुम पहले से विवाहित है। इसके बाद वह उसे छोड़कर वापस इंद्रपुर आ गई। बताया जाता है कि हुकुम दो बार उसे लेने पहुंचा, लेकिन युवती ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया।

इसके बाद युवती अपनी बुआ के यहां जलगोन चली गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि हुकुम 25 से 30 लोगों के साथ पहुंचा और उसे अपने साथ ले गया। उसका कहना था कि उसने बेजा दिया है, इसलिए युवती पर उसका अधिकार है।

निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित बेजा प्रथा आदिवासी समाज की एक परंपरा मानी जाती है। इसके तहत युवक-युवती की सहमति से विवाह संबंध स्थापित होने के बाद समुदाय और पंचों द्वारा उसे मान्यता दी जाती है। बाद में दोनों पक्षों के परिवारों के बीच आपसी समझौते और दंड राशि के माध्यम से संबंध को अंतिम रूप दिया जाता है।

शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म

माही की गूंज, खंडवा।

खालवा क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहाँ एक 16 वर्षीय किशोर पर दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा के साथ अनाचार करने का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया है और उसे बाल सुधार गृह (बाल संप्रेषण गृह) भेज दिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता और आरोपी दोनों एक ही गाँव के निवासी हैं और पूर्व से परिचित थे। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि 5 जुलाई को आरोपी ने उसे दूरभाष (फोन) कर अपने मित्र के जन्मदिवस उत्सव में चलने के लिए कहा था। विश्वास करके छात्रा उसके साथ चली गई। आरोपी उसे गाँव के समीप एक खेत में बनी टपरी (झोपड़ी) में ले गया, जहाँ उसने विवाह का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बाद भयभीत पीड़िता ने अपने परिवार को पूरी बात बताई। इसके बाद मंगलवार को परिजन पीड़िता को लेकर खालवा थाने पहुँचे और मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।

खालवा थाना प्रभारी जगदीश सिंधिया ने बताया कि पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी नाबालिग के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (''पॉक्सो कानून'') की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर बाल सुधार गृह भेजने की वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। थाना प्रभारी ने आगे बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण (मेडिकल जांच) करवा लिया है और मामले की विस्तृत जाँच जारी है। कानून के नियमों के तहत नाबालिगों से जुड़े मामलों में पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जा रही है।

झमाझम बारिश : स्कूल परिसर में भरा पानी, खेती-किसानी प्रभावित

माही की गूंज, खरगोन।

बुधवार सुबह से मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह करीब साढ़े नौ बजे शुरू हुई तेज और रुक-रुककर होने वाली बारिश का सिलसिला देर तक जारी रहा। जिले में अब तक औसतन 240 मिलीमीटर (करीब 9.4 इंच) वर्षा दर्ज की जा चुकी है। लगातार हो रही बारिश का असर विद्यालयों, यातायात और खेती-किसानी पर दिखाई दे रहा है।

तेज बारिश के कारण कुकडोल स्थित एक विद्यालय परिसर में जलभराव की स्थिति बन गई। विद्यालय पहुंचने वाली छात्राओं को पानी से होकर गुजरना पड़ा, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कई अभिभावक भी बच्चों को सुरक्षित विद्यालय पहुंचाने के लिए साथ आए। वर्षा के कारण सुबह के समय आवागमन भी प्रभावित रहा।

पिछले दो-तीन दिनों से हो रही लगातार वर्षा के कारण जिले में कृषि कार्य भी प्रभावित हो गया है। किसान अरविंद जायसवाल ने बताया कि गर्मी की कपास फसल में तेजी से खरपतवार बढ़ रही है। लगातार गीली मिट्टी के कारण खेतों में कृषि उपकरणों का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे फसल की देखरेख में कठिनाई आ रही है।

मौसम विभाग ने खरगोन जिले में आगामी तीन दिनों तक तेज वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने नागरिकों से आवश्यक सावधानी बरतने और मौसम संबंधी ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी है। लगातार वर्षा को देखते हुए निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनने की आशंका भी व्यक्त की गई है।

लगातार हो रही वर्षा ने जिले में जनजीवन के साथ-साथ खेती-किसानी को भी प्रभावित किया है। मौसम विभाग के आगामी तीन दिनों के पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

सवाल नैतिकता और जवाबदेही का भी है

यह सही है कि 'कॉकरोच पार्टी' द्वारा चलाये जा रहे देश के शिक्षामंत्री-विरोधी अभियान में दिल्ली के जंतर-मंतर में उतने युवा इकट्ठा नहीं हो रहे, जितनों की आयोजकों को आशा थी, पर सही यह भी है कि देश के युवाओं के संदर्भ में इस अभियान को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। युवा देश के शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि 'नीट' और 'सीबीएससी' जैसी परीक्षाओं में हो रही धांधली शिक्षामंत्री की असफलता का प्रतीक है। 'नीट' की परीक्षा के संदर्भ में देश के पंद्रह से अधिक युवाओं द्वारा की गई आत्महत्याएं निश्चित रूप से एक गंभीर मसला है और इस बारे में सरकार की लगभग चुप्पी पर सवाल उठने ही चाहिए। सवाल उठ भी रहे हैं, पर जिन्हें जवाब देने हैं वे बचाव के रास्ते खोज रहे हैं।

ऐसा ही एक रास्ता शिक्षामंत्री ने खोजा है। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्ष द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन से बचाव के लिए देश में आपातकाल लागू करने का रास्ता खोजा था। बावजूद इसके कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने यह दावा किया था कि उसका यह कदम देश के संविधान द्वारा दिये गये अधिकार के अनुकूल था, आपातकाल लागू करने की यह कार्रवाई देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाली थी। देश के शानदार जनतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय था यह। तत्कालीन सरकार द्वारा अपने उठाये गये इस कदम के बचाव में बहुत कुछ कहा गया था, पर इसका औचित्य सिद्ध करने का कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता था।

स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी अपनी गलती का अहसास हो गया था। आपातकाल लागू करने के इक्कीस महीने बाद, मार्च 1977 में उन्होंने अपना उठाया गया कदम वापस ले लिया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी भी थी। कांग्रेस के अब के नेता, राहुल गांधी ने भी उस घटना के लगभग पचास साल बाद, 2021 में, आपातकाल लागू करने को 'गलती' मानकर खेद व्यक्त किया था। लेकिन इस स्वीकारोक्ति के बाद भी यह कलंक तो कांग्रेस के माथे पर लगा ही रहा कि उसने आपातकाल लागू करके एक जनतंत्र-विरोधी कार्रवाई की थी। कांग्रेस के विरोधी दल, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, अक्सर कांग्रेस के इस 'काले कारनामे' का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते रहे हैं। अपने बचाव में कांग्रेस इस 'गलती' को भुला देने की बात कहती रही है। पर कांग्रेस-विरोधी इसे एक हथियार की तरह काम में लेते रहे हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने आपातकाल की बरसी के अवसर पर, इस हथियार को अपने बचाव का साधन बनाने की कोशिश की है। अपने खिलाफ चल रहे 'शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो' आंदोलन की आलोचना करते हुए उन्होंने कांग्रेस को 'जनतंत्र-विरोधी' बताकर अपना बचाव किया है। इसी संदर्भ में 'एनसीईआरटी' की किताबों में आपातकाल के बारे में जोड़े गये अध्याय का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को, और भावी पीढ़ियों को, आपातकाल की जानकारी देना जरूरी है। अब पहली बार कक्षा नौ की सामाजिक विज्ञान की किताब में इसे 'भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रमुख चुनौतियों' के रूप में शामिल किया गया है।

हालांकि 12वीं की किताब में पहले ही यह विषय जोड़ा जा चुका था, और जब यह जोड़ा गया तब सत्ता में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। ऐसे में इस विषय को उठाकर शिक्षामंत्री आखिर क्या पाना चाहते हैं? शायद 'नीट' की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर हो रही अपनी आलोचना से ध्यान बंटाने की एक कोशिश हो यह। शायद उन्हें लग रहा हो कि इस तरह ध्यान बंटा कर वे अपना कुछ बचाव करने में सफल हो सकते हैं!

'एनसीईआरटी' की नौवीं कक्षा की किताबों में भी आपातकाल का अध्याय जोड़ने का बचाव करते हुए शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां यह जान और समझ सकें कि ऐसा कोई काला अध्याय कभी लिखा गया था। भविष्य में ऐसा कुछ न हो इसके लिए आज के विद्यार्थियों को यह पढ़ाया जाना जरूरी है।

निश्चित रूप से भावी पीढ़ियों को ऐसी बातों का पता होना चाहिए। 'एनसीईआरटी' की किताब में ऐसे अध्याय का होना कतई गलत नहीं है। गलत यह है कि ध्यान बंटाने के साधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 'नीट' और 'सीबीएससी' की परीक्षाओं में हो रही धांधली की जांच की दुहाई दी जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा, इसका आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन सवाल किसी के जिम्मेदारी लेने का भी है। सवाल नैतिकता का भी है। नैतिकता का तकाजा है कि पर्चों की गड़बड़ी के चलते हुई आत्महत्याओं की जिम्मेदारी कोई तो ले। सन् 2021 से लेकर 2026 के बीच इस संदर्भ में 93 छात्रों की आत्महत्याओं के मामले सामने आये हैं। इसी वर्ष, यानी 2026 में, कम से कम चौदह छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। आखिर कोई तो जिम्मेदार होगा इन घटनाओं के लिए।

दिल्ली में जंतर-मंतर पर, और देश में कई अन्य शहरों में भी, परीक्षाओं में हुई धांधली के आरोप में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। हो सकता है भाजपा-विरोधी दल स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हों। पर इससे स्थिति की गंभीरता और भयावहता कम नहीं हो जाती। चूंकि मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ है इसलिए स्वाभाविक है शिक्षा मंत्री से जवाब मांगा जाये। पर, दुर्भाग्य से, शिक्षामंत्री मौन साधे बैठे हैं। बोले भी हैं तो ऐसी बात जो ध्यान बंटाने का माध्यम लग रही है। ध्यान बंटाना उनकी राजनीतिक विवशता हो सकती है, पर नैतिकता का तकाजा है कि वे अपने विभाग की कमजोरी स्वीकार करें। पहली बात तो यह कि वे यह मानें कि कुछ नहीं, बहुत कुछ, गलत हुआ है। गलत हुआ है तो कोई तो गुनहगार होगा। किसी की तो जिम्मेदारी बनती है कि यह स्वीकारे कि वह अपना दायित्व नहीं निभा पाया, या दायित्व को समझ नहीं पाया। नैतिकता का ही तकाजा यह भी है कि ऊंची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति पहले कदम उठाये।

यहां वह याद दिलाना गलत नहीं होगा कि इस देश में एक रेलमंत्री ने इसलिए इस्तीफा दे दिया था कि उसके कार्य-काल में दिल्ली से सैकड़ों मील दूर कहीं एक रेल-दुर्घटना हो गयी थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेल-मंत्री लालबहादुर शास्त्री ने अपना पद छोड़ दिया था। यह वर्ष 1956 की बात है। तमिलनाडु के अरियालुर में भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गयी थी। शास्त्रीजी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का हवाला दिया था। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू इस्तीफा स्वीकार करने के अनिच्छुक थे। शास्त्रीजी की जिद थी। वे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर इस्तीफा देना चाहते थे। अंततरू नेहरू ने संवैधानिक औचित्य के दृष्टिकोण से उदाहरण स्थापित करने के महत्व का हवाला देते हुए अपने रेल-मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब क्यों नहीं कोई अपना इस्तीफा देकर उदाहरण स्थापित करता? अब तो यह कहा जाता है कि हमारी सरकार में इस्तीफा देने की परम्परा नहीं है! होनी चाहिए ऐसी परम्परा। संवैधानिक औचित्य के महत्व को समझा जाना जरूरी है।

विश्वनाथ सचदेव

जहां तक भावी पीढ़ियों को 'आपातकाल' जैसे प्रकरण से परिचित कराने की बात है, इसे पाठ्यक्रम में शामिल होना ही चाहिएद्द किसी को दोषी सिद्ध करने के लिए नहीं, यह बताने के लिए कि देश के इतिहास में ऐसे काले अध्याय आनेवाली पीढ़ियों को उचित के पक्ष में खड़े होने की महत्ता समझाते हैं, अनुचित के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। लगभग पांच दशक पहले देश ने जिस आपातकाल को झेला था, वह हमेशा याद दिलाता रहेगा कि तानाशाही कभी भी सिर उठा सकती हैं, पर ऐसी कोई भी तानाशाही अपराजेय नहीं होती।

सहकारिता सदस्यता महाअभियान में रचा नया कीर्तिमान, जिले को मिला प्रथम स्थान

माही की गूंज, आलीराजपुर।

सहकारिता से समृद्धि योजना के अंतर्गत सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित सदस्यता महाअभियान में आलीराजपुर जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिले को 5 हजार नवीन सदस्य जोड़ने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध 6 हजार 196 नए सदस्यों को सहकारिता से जोड़कर 124 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गई।

जिला कलेक्टर श्रीमती नीतू माथूर के मार्गदर्शन में सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक झाबुआध्आलीराजपुर के संयुक्त तत्वावधान में 14 अप्रैल से विशेष सदस्यता अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान जिले की सभी बी-पैक्स समितियों, उचित मूल्य दुकानों, ग्राम पंचायतों एवं सहकारी संस्थाओं तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सहकारी सप्ताह के समापन अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासक श्री महेंद्र सिंह यादव द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक झाबुआध्आलीराजपुर के महाप्रबंधक श्री आरजू इकबाल खान को प्रथम पुरस्कार, प्रशस्ति-पत्र एवं शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस उपलब्धि में सहकारिता विभाग के उपायुक्त श्री जी.एल. सोलंकी, बैंक के नोडल अधिकारी श्री हर्षवर्धन गुप्ता, जिले की समस्त बी-पैक्स समितियों, बैंक प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर कलेक्टर श्रीमती नीतू माथूर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती संघमित्रा गौतम ने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सहकारी संस्थाओं के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता एवं उत्साह के साथ कार्य करते हुए सहकारिता आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने की अपेक्षा व्यक्त की।

सीवेज चेंबर में दम घुटने से एक मजदूर की मौत

माही की गूंज, उज्जैन।

महाकाल की नगरी उज्जैन के पीपली नाका इलाके में मंगलवार को एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हो गया। यहां एक सीवेज चेंबर ब्लॉक क्लीयर करने उतरे तीन सफाईकर्मी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। हादसे में दम घुटने से एक सफाई कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान अशोक (निवासी सालाखेड़ी, आलोट, रतलाम) के रूप में हुई है। वह चेंबर में ब्लॉक क्लियर करने उतरा था, तभी अचानक पैर फिसलने और जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गया। उसे बचाने उतरे दो साथी गोपाल डाबी और रमेश चौहान भी गैस के कारण वहीं अचेत हो गए।

हादसे के वक्त वहां से गुजर रहे उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने जब चेंबर के पास भीड़ देखी, तो उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई। एसपी ने पुलिस टीम और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों अचेत कर्मचारियों को बाहर निकलवाकर अस्पताल भिजवाया।

सुपरवाइजर चंद्रकांत शुक्ला की अगुवाई में जेटिंग मशीन लेकर टीम चेंबर की ब्लॉकेज खोलने पीपली नाका पहुंची थी। सुपरवाइजर आगे के चेंबर चेक करने गया, इसी दौरान अशोक बिना सुरक्षा उपकरणों के चेंबर के अंदर उतरा और गैस चढ़ने से गिर गया। अशोक को बचाने उतरे गोपाल और रमेश भी अंदर ही बेहोश हो गए। लौटकर सुपरवाइजर ने शोर मचाया। मौके से गुजर रहे एसपी प्रदीप शर्मा ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। डॉक्टरों ने अशोक को मृत घोषित कर दिया, जबकि गोपाल और रमेश का आईसीयू में इलाज जारी है। जीवाजीगंज थाना प्रभारी प्रतीक शर्मा ने बताया कि अभी घायल कर्मचारियों के बयान दर्ज होना बाकी है। यदि ठेकेदार कंपनी की ओर से सुरक्षा मानकों में लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी।

वन मंडल की बड़ी कार्यवाही

माही की गूंज, धार।

वन मंडल अधिकारी विजयानंथम टी.आर. के मार्गदर्शन में धार वन मंडल द्वारा वन भूमि संरक्षण एवं अतिक्रमण नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। वन विभाग के मैदानी अमले ने जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, ग्राम वन समिति, स्थानीय जन प्रतिनिधियों के सहयोग से जनवरी 2026 से मई 2026 के बीच 07 वन परिक्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 589.63 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी 2026 से मई 2026 तक मुक्त कराये गये अतिक्रमण के तहत परिक्षेत्र धार में 100.55 अतिक्रमण क्षेत्र का रकबा (हे0 में) मुक्त कराया गया है। इसी प्रकार धामनोद में 35.10, मांडव में 50.78, सरदारपुर में 50.62, टाण्डा में 93.76, बाग में 202.82 तथा कुक्षी में 56.00 अतिक्रमण क्षेत्र का रकबा (हे0 में) मुक्त कराया गया है। इस तरह कुल 589.63 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। वन विभाग के अनुसार यह पूरी कार्रवाई अत्यंत शांतिपूर्ण, विधिसम्मत एवं सुनियोजित तरीके से संपन्न की गई। विभाग का उद्देश्य वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर उसका पुनर्वनीकरण करते हुए प्राकृतिक वन संपदा का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर वर्षाकाल 2026 में सागौन (रूट-शूट) रोपण किया जाएगा। इसके लिए धार वन मंडल स्तर पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर वन अधिकारियों एवं मैदानी कर्मचारियों को वैज्ञानिक पद्धति से सागौन रूट-शूट रोपण, पौध संरक्षण एवं रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ताकि रोपण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। वन विभाग द्वारा आमजन से अपील की है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। वन भूमि सार्वजनिक एवं प्राकृतिक संपदा है, जिसका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वन मंडल अधिकारी श्री विजयानंथम टी. आर. ने कहा कि वन भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति वन भूमि पर अतिक्रमण करता है अथवा ऐसा करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं शासकीय संपत्ति को नुकसान पुहंचाने के फलस्वरूप वन अपराध प्रकरण के साथ एफ0आई0आर भी दर्ज कर विधिक प्रावधानों के अंतर्गत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धार वन मंडल द्वारा वन संरक्षण, अतिक्रमण नियंत्रण एवं व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने तथा वन संपदा के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए अभियान निरंतर जारी रहेगा।

जयकारों से गूंज उठी ऐतिहासिक भोजशाला

माही की गूंज, धार।

धार की ऐतिहासिक भोजशाला में मंगलवार को नियमित सत्याग्रह श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के माहौल में संपन्न हुआ। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वाग्देवी के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा।

श्रद्धालुओं ने मां वाग्देवी की आरती उतारी, सामूहिक रुप से हनुमान चालीसा का पाठ किया और जयकारों से पूरा भोजशाला परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर गर्भगृह को विशेष रूप से सजाया गया था, जिससे मंदिर का वातावरण और भी आकर्षक नजर आया।

नियमित सत्याग्रह में इस बार महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के वर्ष 1952 से जुड़े संस्थागत सदस्य रमेशचंद्र परमार (मिथ्यावादी) तथा लंबे समय से भोजशाला मुक्ति आंदोलन से जुड़े सत्यनारायण शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। दोनों ने मां वाग्देवी की आरती की।

इसके बाद समिति की ओर से दोनों वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भोजशाला की मुक्ति के लिए दशकों तक समाज ने संघर्ष किया है। अनेक लोगों के त्याग, समर्पण और लगातार चले सत्याग्रह के परिणामस्वरुप आज यहां नियमित पूजा-अर्चना और आरती का क्रम जारी है। देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु मां वाग्देवी के दर्शन के लिए धार पहुंच रहे हैं, जिससे भोजशाला की धार्मिक पहचान लगातार मजबूत हो रही है।

सरस्वती लोक का निर्माण कार्य जल्द धरातल पर प्रारंभ हो

परमार व शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि भोजशाला को उसके प्राचीन और गौरवशाली स्वरूप में विकसित किया जाए। उन्होंने मांग की कि जिस सरस्वती लोक की घोषणा की गई है, उसका कार्य भी जल्द धरातल पर शुरु होना चाहिए। उनका कहना था कि इससे न केवल भोजशाला का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वैभव और अधिक निखरेगा, बल्कि धार को देशभर में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रुप में नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने का प्रयास होगा।

सत्याग्रह ने समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया

समिति पदाधिकारियों ने कहा कि नियमित सत्याग्रह ने समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। भविष्य में भी इसी तरह समाज एकजुट होकर भोजशाला के गौरव को और बढ़ाने के लिए प्रयास करता रहेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में सत्याग्रह और पूजा-अर्चना में शामिल होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भोज उत्सव समिति के संरक्षक कृष्णा नागर, विश्वास पांडे, मार्गदर्शक राजेश शुक्ला, अध्यक्ष सुरेश जलोदिया, महामंत्री सुमित चौधरी, महाप्रबंधक हेमंत दौराया, सत्याग्रह प्रमुख एवं भोज मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में समिति पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मातृशक्ति और श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना रहा।

निर्मोही अखाड़ा ने महंत रविंद्र पुरी को दिया समर्थन

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले में चल रही सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की बीच निर्मोही अणि अखाड़ा ने महंत रविंद्र पुरी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। चार महीने पहले निर्मोही अखाड़ा ने महंत रविंद्र पुरी के नेतृत्व को स्वीकार करने से इनकार किया था।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में लंबे समय से नेतृत्व को लेकर दो गुट आमने-सामने हैं। एक पक्ष निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी के नेतृत्व में सक्रिय है, जबकि दूसरा पक्ष महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी को अपना अध्यक्ष मानता है। दोनों गुट लगातार अपने-अपने साथ अधिक अखाड़ों के होने का दावा करते रहे हैं।

मंगलवार रात उज्जैन में हुई बैठक के बाद निर्मोही अखाड़ा ने घोषणा की कि वह आगामी नासिक कुंभ और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में महंत रविंद्र पुरी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ रहेगा।

निर्मोही अणि अखाड़ा की बैठक की अध्यक्षता महंत रविंद्र पुरी ने की। बैठक में श्रीमहंत मदन मोहन दास, श्रीमहंत भगवान दास, श्रीमहंत सीताराम दास समेत अखाड़े के पंच शामिल हुए। बैठक में आठ अखाड़ों ने उनका समर्थन दोहराया और अब निर्मोही अखाड़ा भी इस समूह का हिस्सा बन गया है।

निर्मोही अणि अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत सीताराम दास ने कहा कि परिषद को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा था। उनके मुताबिक प्रयागराज कुंभ का संचालन भी महंत रविंद्र पुरी के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने बताया कि विचार-विमर्श के बाद निर्मोही अखाड़ा ने परिषद को अपना समर्थन देने और भविष्य के कुंभ आयोजनों में साथ रहने का औपचारिक निर्णय लिया।

समर्थन मिलने के बाद महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि उनके साथ जूना, आह्वान, अग्नि, निरंजनी, आनंद, पंच निर्मोही, निर्मल और बड़ा उदासीन (रघुमुनि) अखाड़ा जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब रामदल और शंभू दल एक साथ आ गए हैं और सभी सन्यासी तथा वैष्णव संतों को एक मंच पर लाने का प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने विरोधी गुट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि असली अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद वही है, जिसका नेतृत्व उनके पास है।

इससे पहले 22 मार्च को महानिर्वाणी, अटल, निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी अणी, बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़े के संतों ने महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए उनके नेतृत्व में कुंभ आयोजन कराने की घोषणा की थी।

हरिद्वार कुंभ 2021 के बाद अखाड़ा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष नरेंद्र गिरि के निधन से नेतृत्व का प्रश्न अनसुलझा रह गया। नए अध्यक्ष के चयन पर सहमति नहीं बनने के कारण परिषद दो हिस्सों में बंट गई। एक ओर जूना और निरंजनी अखाड़े ने महंत रविंद्र पुरी का समर्थन किया, जबकि दूसरी ओर वैष्णव और बैरागी परंपरा से जुड़े अखाड़ों ने दूसरे रविंद्र पुरी के नेतृत्व को स्वीकार किया। तब से दोनों गुट स्वतंत्र रूप से फैसले लेते रहे हैं और परिषद एकजुट स्वरूप में सामने नहीं आ सकी।

स्टेट हाईवे होंगे गोवंश मुक्त

माही की गूंज, उज्जैन।

देश में सड़कों पर घूमते और बैठते बेसहारा गोवंश के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने गोवंश प्रबंधन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है, जिसे शासन की मंजूरी मिलते ही लागू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था का लाभ उज्जैन जिले के स्टेट हाईवे को भी मिलेगा, जहां धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण यातायात और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण आए दिन गोवंश सड़क पर दिखाई देता है।

उज्जैन जिले से जुड़े विभिन्न स्टेट हाईवे पर अक्सर बेसहारा गोवंश सड़क पर बैठा रहता है। विशेष रूप से बारिश के मौसम में सड़कें जल्दी सूखने के कारण गोवंश बड़ी संख्या में हाईवे पर आ जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कई बार वाहन चालक गोवंश को बचाने के प्रयास में स्वयं दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।

नई एसओपी के तहत स्टेट हाईवे के किनारे हर पांच किलोमीटर पर टीन शेड वाली गोशालाएं विकसित की जाएंगी, जहां बेसहारा गोवंश को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा सड़क किनारे विशेष चबूतरे बनाए जाएंगे ताकि पशु सड़क पर बैठने के बजाय निर्धारित स्थानों पर रहें। प्रत्येक क्षेत्र के लिए रेस्क्यू वाहन भी उपलब्ध रहेगा, जो सड़क पर मिले गोवंश को पकड़कर सुरक्षित गौशाला तक पहुंचाएगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस एजेंसी या कंपनी को सड़क निर्माण का कार्य सौंपा जाएगा, वही इन गोशालाओं, चबूतरों और अन्य व्यवस्थाओं के निर्माण एवं संचालन की जिम्मेदारी भी निभाएगी। स्थानीय प्रशासन और संबंधित निकायों के साथ समन्वय कर बेसहारा गोवंश का प्रबंधन किया जाएगा। भविष्य में बनने वाले सभी नए स्टेट हाईवे के टेंडर में इन व्यवस्थाओं को अनिवार्य शर्त के रूप में शामिल किया जाएगा।

प्रदेश सरकार का मानना है कि यदि गोवंश को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी और पशुओं का भी संरक्षण होगा। उज्जैन जैसे धार्मिक शहर में, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु महाकाल दर्शन के लिए पहुंचते हैं और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी भारी यातायात रहता है, यह योजना सड़क सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

यदि शासन इस एसओपी को अंतिम मंजूरी दे देता है तो मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा, जहां सड़क निर्माण परियोजनाओं के साथ गोवंश प्रबंधन को भी संस्थागत रूप से जोड़ा जाएगा। इससे प्रदेश के साथ-साथ उज्जैन जिले के स्टेट हाईवे पर भी सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और पशु संरक्षण को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट से थम गई 12 दिन के मासूम की सांसे

माही की गूंज, धार।

जिले के धामनोद क्षेत्र से एक ऐसा दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। महज 12 दिन का एक नवजात, जो अपने पिता की गोद में घर के भीतर सो रहा था, अचानक आकाशीय बिजली की तेज गड़गड़ाहट से इस कदर घबरा गया कि उसकी सांसें थम गईं। दावा किया जा रहा है कि बच्चे के शरीर पर बिजली गिरने का कोई निशान नहीं था, लेकिन तेज धमाके के बाद उसकी मौत हो गई। यह घटना अब कई सवाल खड़े कर रही है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

धामनोद के समीप ग्राम पंचायत फरसपुरा के सिमराली भावड़िया अवार गांव में मंगलवार शाम करीब चार बजे हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। मृतक मासूम का जन्म 26 जून को गुजरी शासकीय अस्पताल में हुआ था। जन्म के महज 12 दिन बाद ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं।

परिजन के अनुसार मंगलवार शाम क्षेत्र में तेज बारिश हो रही थी। बच्चे के पिता संदीप अपने नवजात बेटे को गोद में लेकर घर के भीतर सुला रहे थे। इसी दौरान अचानक बेहद तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली कड़की। गड़गड़ाहट इतनी भयावह थी कि पूरा घर कांप उठा। परिजन जब तक कुछ समझ पाते, बच्चे की हालत बिगड़ चुकी थी। तत्काल उसे धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉ. श्वेता सांवले ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्चे के शरीर पर बिजली गिरने या जलने के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। ऐसे में यह जांच का विषय बन गया है कि आखिर मौत का वास्तविक कारण क्या था।

जानकारों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति पर सीधे बिजली नहीं गिरी हो, तब केवल गड़गड़ाहट की आवाज से मौत होना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। चिकित्सकीय दृष्टि से भी यह मामला असामान्य है। संभावना जताई जा रही है कि तेज धमाके के कारण बच्चे को अचानक गंभीर शारीरिक प्रतिक्रिया या कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, हालांकि इसकी पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी।

गांव में घटना के बाद शोक का माहौल है। जिस घर में 12 दिन पहले किलकारियां गूंजी थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है। मां रीना का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पिता संदीप सदमे में हैं। पूरे गांव के लोग इस घटना को अविश्वसनीय बताते हुए परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं।

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर मौत के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। यदि आवश्यकता पड़ी तो विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय भी ली जाएगी। फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार केवल आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट से नवजात की मौत का यह संभवतः पहला मामला है।

बेटी के घर से लौटते समय नाला पार करते हुए हुआ हादसा

धार जिले में मंगलवार को मानसून की तेज वर्षा ने जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी, वहीं एक परिवार पर दुखों का पहाड़ भी टूट पड़ा। दोपहर बाद करीब सवा घंटे तक हुई मूसलधार वर्षा के बीच उफनते नाले को पार करते समय एक 50 वर्षीय मजदूर बह गया। उसका शव कई किलोमीटर दूर ग्राम लबरावदा के पास नाले के किनारे मिला। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी।

घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सामने आने के बाद स्वजन को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद वे जिला अस्पताल पहुंचे और शव की पहचान देवीसिंह पुत्र हिंदूसिंह (50) निवासी तोरनोद के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरु कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

स्वजन ने बताया कि देवीसिंह अपनी बेटी के घर ग्राम गरड़ावद गए थे। वापस लौटते समय तेज वर्षा के कारण नाले में अचानक पानी बढ़ गया। इसी दौरान बाइक सहित नाला पार करने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव में संतुलन बिगड़ गया और वे पानी में बह गए। उनकी बाइक भी नाले में बह गई, जिसका देर शाम तक पता नहीं चल सका। देवीसिंह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके तीन बेटे और तीन बेटियां हैं। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। नौगांव पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

लंबे इंतजार के बाद मिल रही झाबुआ-रतलाम रोड की सौगात, पहली शुरूआती बारिश में ही दम तोड़ती दिखाई दे रही सड़क

निर्माण एजेंसी की लापरवाही और भ्रष्टाचार खुलेआम देखने को मिल रहा है

बनने के बाद राहत नही, आफत ही बना रहेगा झाबुआ-रतलाम रोड

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसुरी

वैसे इस देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई कमी नही है। खास कर जब बात सड़क निर्माण को लेकर की जाए। स्थितियां इतनी गंभीर है कि, सरकार और सरकारी तंत्र हथेली को दिल्ली और अंगूठे को कुतुब मिनार बताने में जरा भी गुजरे नहीं करते। बातें तो विदेश टेक्नोलोजी से निर्माण करने की होती है लेकिन परिणाम गधे के सिर से सिंग की तरह गायब ही नजर आते है। या यूं कहले कि, विदेशी तकनीक भारत की पृष्ट भूमि पर हमेशा विफल ही होती नजर आती है। प्रदेश में भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि, सड़के मंजूर होती, रुपया स्वीकृत होकर निकल जाता और सड़क जमीन से ही गायब नजर आती। ऐसे बहुत से उदाहरण है जो हमेशा प्रदेश की जनता को चौकाकर रख देते है। मगर भ्रष्टाचार है कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता नजर आता है।

शुरूआती हल्की बारिश में ही नव निर्मित सड़क की साइड पट्टी में इस तरह आ गई गहरी दरारें, तेज बारिश में बह जाने की पूरी संभावना।

झाबुआ-रतलाम मार्ग की नव निर्मित सड़क पर कस्बो और बस स्टॉप पर बने कांक्रीट रोड पर भी निर्माण पूर्ण होने के पूर्व ही दिखने लगी दरारें।

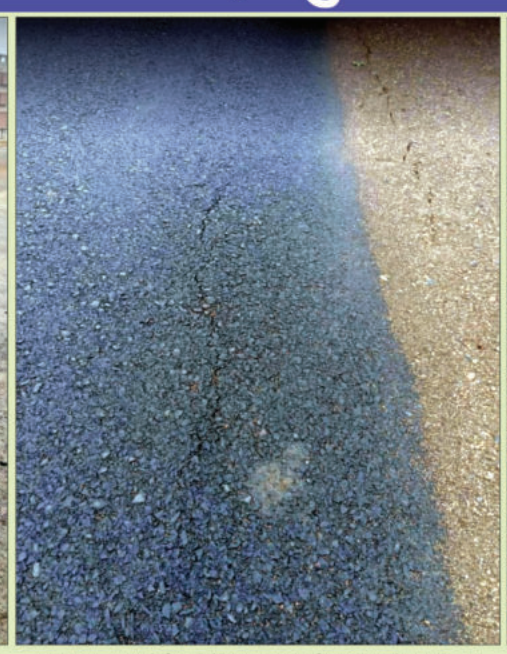

झाबुआ-रतलाम मार्ग की नव निर्मित सड़क पर डामरीकरण पर कई सवाल है, नया निर्माण होने के बावजूद डामर सड़क मे भी दरारे साफ दिखाई दे रही है।

कई जगहो पर बारिश के शुरूआती दौर मे ही सड़क की साइड पट्टी से मिट्टी का कटाव इतना गहरा हो गया है कि यह दुर्घटना को न्यौता दे रहा है।

बात सड़क निर्माण को लेकर हो रही है तो प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सड़क झाबुआ से रतलाम की बात होना भी जरूरी है। इस सड़क ने कई परियोजनाओं में डूबकी लगाई लेकिन यह सड़क सात सालों में कभी बन नहीं पाई। पहले टू लेन, फिर फोर लेन और अब फिर से टू लेन हो गई। हांलाकि जमीन पर इस तरह का कुछ होता दिखाई नही दिया। अब वर्तमान में जब यह सड़क रतलाम से झाबुआ तक टू लेन बन रही है तो स्थिति और अचंभित करने वाली नजर आ रही है।

2018 में सबसे पहले इस मार्ग को फोरलेन बनाने की कवायदें शुरू हुई। सर्वे भी शुरू हुआ था और इसे नेशनल हाइवे अर्थोरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को सौंप दिया गया था। लंबा समय गुजरा लेकिन इस सड़क निर्माण का मुहुर्त नहीं निकल पाया। परिणाम योजना विफल हो गई। अप्रैल 2023 में इसे एनएच-147 ई घोषित कर भारतमाला फेज-2 में शामिल किया गया। इसे 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हालात फिर से नौ दिन चले अढ़ाई कोस रहे और यहां भी यह सड़क जमीन पर नहीं उतर सकी। यह योजना भी पूरी तरह से विफल ही साबित हुई।

2025 में इस प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) द्वारा टू लेन विथ पेव्ड शोल्डर (पेव्ड शोल्डर के साथ टू-लेन) के रूप में अपग्रेड करने के लिए नए सिरे से पैकेज जारी किए गए।

लंबी जद्दोजहद के बाद अंततः एमपीआरडीसी यानी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने रतलाम-झाबुआ के 100 किमी लंबे रोड पर टू लेन बनाने की 325 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दे दी। इस रोड से प्रतिदिन करीब 5 हजार दो व चार पहिया वाहन निकलते है। फिलहाल यह रोड निर्माणाधीन है, कई हिस्से बन चुके है तो कई हिस्सों में निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण से पहले यह सड़क पूरी तरह से जर्जर हो रही थी। रोड का निर्माण रतलाम के सालाखेड़ी से लेकर झाबुआ तक होना है। निर्माण ऐजेंसी को 31 दिसंबर 2027 तक कार्य को पूरा करने का समय दिया गया है। पहले यह रोड टू लेन, फिर फोरलेन व अंत में टू लेन बनाने का निर्णय लिया गया।

अब वर्तमान स्थिति इस सड़क की यह है कि, जगह-जगह भ्रष्टाचार नजर आने लगा है। वैसे तो रतलाम से बामनिया के बीच निर्माण की स्थिति कुछ ऐसी है कि हर रोज वाहन चालकों को अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना पड़ रहा है। थांदला से झाबुआ के बीच भी स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही है। निर्माण एजेंसी इस निर्माण कार्य को लेकर कतई गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। निर्माण के दौरान मार्ग का डायवर्सन हो या फिर सड़क की एक पट्टी चालू हो या बंद कहीं पर कोई निशानदेही या संकेतक नही है। रतलाम से झाबुआ तक पूरे मार्ग में अधिकतर जगह ऐसी है जो खतरनाक है, लेकिन निर्माण एजेंसी ने कहीं कोई संकेतक नहीं लगा रखे है। नतीजन इस निर्माणाधीन मार्ग पर आए दिन लंबे-लंबे जाम वाहन चालकों को झेलना पड़ रहे है। अब जबकि वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है तो इस निर्माणाधीन मार्ग की स्थिति का अंदाजा स्वतः ही लगाया जा सकता है कि, हालात कैसे होंगे। निर्माणाधीन सड़क पर कीचड़, फिसलन, दलदल जैसे कई स्पाट बनते जा रहे है। मगर इसकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। सरकार और तंत्र निर्माण एजेंसी को कार्य सौंपकर छुटपल्ले हो गए है।

खवासा से थांदला के बीच यह सड़क पूरी तरह से बन चुकी हैं, लेकिन पहली ही बारिश में इस नव निर्मित सड़क की पोल खुलती दिखाई दे रही है। 10 मीटर चौड़ी यह सड़क वैसे तो पूरी तरह से डामर रोड है लेकिन कस्बों व बस स्टॉप के आसपास इस सड़क पर कांक्रीट रोड बनाया गया है। विडम्बना यह कि, पहली ही बारिश में इस सड़क का मेकअप उतरता दिखाई दे रहा है और यह सड़क भ्रष्टाचार का गुणगान करती नजर आ रही है। महज कुछ महीनों पहले हुआ नव निर्माण पहली ही बारिश में बहता नजर आ रहा है। सड़क कई जगहों से बीच से ही फट चुकी है और उसमें साफ तोर पर बड़ी दरारे दिखाई देने लगी है। वैसे तो इस सड़क के दोनों और पेव्ड शोल्डर होना चाहिए थे लेकिन निर्माण एजेंसी ने इसकी दोनों साइड मिट्टी से ही भर दी। नतीजा यह हुआ कि, पहली ही बारिश में सड़क की दोनों साइडों से मिट्टी बह कर चली गई। अब आगे जब बारिश होगी तो सीधे तौर पर पानी, नई बनी सड़क को काटेगा और अपने साथ बहा ले जाएगा।

जबकि इस प्रोजेक्ट को मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ने टू लेन विथ पेव्ड शोल्डर (पेव्ड शोल्डर के साथ टू-लेन) के रूप में अपग्रेड करने के लिए नए सिरे से पैकेज जारी किए थे। तो फिर निर्माण एजेंसी ने सड़क के दोनों और सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से ही साइड पट्टियां क्यों भर दी? यह इस सड़क निर्माण में खुला भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। क्योंकि पेव्ड शोल्डर का मतलब ही कुछ और होता है। पेव्ड शोल्डर का मतलब सड़क के मुख्य भाग के दोनों ओर बनी पक्की पट्टियाँ होती हैं। जो डामर या कंक्रीट से बनी होती हैं। यह सड़क को सहारा देती हैं। खराब गाड़ी को यहाँ खड़ा किया जा सकता है। पैदल चलने वाले व साइकिल चालक भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपातकाल में गाड़ियां यहाँ रोकी जाती है। इससे मुख्य ट्रैफिक नहीं रुकता। यह भारी वाहनों के भार से मुख्य सड़क के किनारों को टूटने से बचाता है।

अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण एजेंसी को किस तरह के पेव्ह शोल्डर बनाने थे और निर्माण एजेंसी ने किस तरह से सड़क की साइड पर मिट्टी भर दी है। इसे खुला भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा। यह तो वह स्थिति है जो वर्तमान में सामने आ चुकी है और मात्र पहली बारिश में ही नव निर्मित रतलाम-झाबुआ मार्ग सड़क की पोल खोल दी हैं। अंदाजा लगाईए कि अगर इस वर्ष क्षेत्र में भारी बारिश हुई तो इस नव निर्मित और निर्माणाधीन रतलाम-झाबुआ टू लेन विथ पेव्ह शोल्डर सड़क के क्या हाल होंगे? अगर बारिश अधिक और मुसलाधार होती है तो यह तय है कि रतलाम -झाबुआ टू लेन सड़क का सपना क्षेत्र वासियों के लिए सपना ही साबित होगा। क्योंकि सारे हालात इसी तरफ इंगित कर रहे है।

प्रशासनिक लापरवाही ने दिया बड़े किसान आंदोलन को जन्म

फोरलेन निर्माण में जमीन खोने वाले किसानों को आज तक नहीं मिला नोटिस, जमीन अधिग्रहण शुरू

एसडीएम छुट्टी पर गई या भेजी गई?

माही की गूंज, पेटलावद।
राकेश गेहलोत

टीमरवानी-थांदला-पेटलावद-बदनावर फोरलेन (एनएच-752डी) निर्माण को लेकर क्षेत्र के किसानों में गहरा आक्रोश है। सोमवार को पेटलावद के श्रद्धांजलि चौक पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले आयोजित विशाल सभा में किसानों ने अपनी उपजाऊ भूमि बचाने के लिए आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सभा में महिलाओं का दर्द और चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। महिला किसानों ने सवाल उठाया कि, खेती की जमीन छिनने पर वे अगली पीढ़ी का भरण-पोषण कैसे करेंगी? नीरू योगेंद्र मंडलोई ने क्षेत्र में सरकारी योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि, जमीन के बिना पानी का कोई अर्थ नहीं है। वहीं, गंगा सहित अन्य महिला किसानों ने वर्तमान मुआवजे को नाकाफी बताते हुए कहा कि, इस राशि में दूसरी जगह जमीन खरीदना असंभव है। किसानों ने स्पष्ट मांग की है कि, ग्रामीण क्षेत्र के नियमों के अनुसार उन्हें बाजार मूल्य का चार से पांच गुना मुआवजा दिया जाए। मकान प्रभावितों के लिए केवल मुआवजा ही नहीं, बल्कि समुचित पुनर्वास और आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, भूमि, कुओं, पेड़ों और मकानों का दोबारा निष्पक्ष मूल्यांकन करने तथा फोरलेन की ऊंचाई कम रखने की मांग भी रखी गई है। सभा के बाद थांदला एसडीएम भास्कर गाचले ने किसानों का ज्ञापन लिया।

प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने सरकार पर दोहरी नीति का आरोप लगाते हुए कहा कि, राज्य सरकार के चार गुना मुआवजे के निर्देशों के बावजूद स्थानीय प्रशासन कम दर पर अड़ा है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उचित निर्णय नहीं लिया गया, तो वे जिला कलेक्टर कार्यालय पर ''डेरा डालो-घेरा डालो'' आंदोलन शुरू करेंगे।

इस विरोध प्रदर्शन में महेश चौधरी, कमल सिंह आंजना, राजेंद्र शर्मा, दिनेश शर्मा, महेश ठाकुर, मोहन पाटीदार, कृष्णपाल सिंह राठौर, बच्चूसिंह मेडा, यशवंत मुकाती, अमोल पाटीदार और वरदीचंद पाटीदार सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। प्रशासन की ओर से एसडीओपी अनुरक्ति साबनानी, तहसीलदार अनिल बघेल, थाना प्रभारी निर्भयसिंह भूरिया और नायब तहसीलदार विजेंद्र कटारे ने स्थिति पर नजर बनाए रखी।

मार्किंग करने पहुंच रहे सरकार के लोग

फोरलेन निर्माण में जमीन खो रहे किसानों का आरोप है कि, निर्माण के लिए एनएचआई के लोग निशान लगाने के लिए पहुंच रहे है, कही पेड़ो पर नंबरिंग की जा रही है तो कही खेतों में सीमेंट के पोल लगाए जा रहे है। किसानों के पास गजट नोटिफिकेशन के अलावा कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है। प्रशासन की ओर से कोई नोटिस आज तक किसी किसान को लिखित में नही दिया गया। ऐसे में किसानों ने अपनी बात प्रशासन से लेकर न्यायालय के मंच पर किस आधार पर रखे। प्रशासन पूरी तरह से सरकार की ओर से किसानों के शोषण के लिए काम कर रहा है जबकि उसका काम न्याय दिलाने का है।

बिना पर्याप्त मुआवजे के एक इंच जगह नहीं, कई लोग हो रहे बे घर

किसान नेताओं ने मंच से साफ संदेश देते हुए कहा कि, जब तक सरकार पर्याप्त मुआवजे की बात नहीं करती तब तक एक इंच जमीन सड़क निर्माण में नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं सरकार की गाइड लाइन में केवल मुआवजा राशि वितरण ही नहीं बल्कि उन लोगों की व्यवस्था करने का नियम भी हैं जो जमीन में पूरी तरह बेघर और भूमि हीन हो रहे है। कई लोगों के घर पूरे नष्ट हो रहे है तो कई लोगों की पूरी जमीन जा रही है। सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है, प्रशासन ने उनके लिए कितने मुआवजे की व्यवस्था की है? इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही हैं। जिससे साफ है कि, प्रशासन एक तरफा एनएचआई का एजेंड बन कर काम कर रहा है।

आपत्तियों का निराकरण तक नहीं

अपनी जमीन गवा रहे कई किसानों ने पेटलावद और थांदला अनुविभागीय अधिकारियों को लिखित में आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिनका कोई निराकरण नहीं किया गया। मौके पर प्रशासन ने पहुंच कर किसान की समस्या तक जानने की कोशिश नहीं की, उनकी आपत्ति का क्या हुआ उसकी तक जानकारी नहीं दी गई। उधर पेटलावद एसडीएम से जब भी किसी किसान ओर किसान संगठन ने मुलाकात कर अपनी समस्या बताई उनको एक ही बात कही जा रही है, हमने हमारा काम कर दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते।

सोमवार को किसान संघ के आयोजन से पहले पेटलावद एसडीएम छुट्टी पर चली गई, सूत्रों के अनुसार उनके प्रति किसानों की सतत नाराजी को देखते हुए एसडीएम मीणा को छुट्टी के नाम पर इस आंदोलन से दूर रखा गया क्योंकि किसान अगर एसडीएम को ही ज्ञापन देने पर अड जाते तो स्थिति बिगड़ने के हालत बन जाते क्योंकि किसी भी स्थिति में एसडीएम किसानो के बीच ज्ञापन लेने नहीं जाती ओर हर बार की तरह अपने अधीनस्थों को ही आगे करती। बताया जा रहा है जिला प्रशासन ने स्थिति को भांपते हुए थांदला एसडीएम को ज्ञापन लेने की जिम्मेदारी सौंपी ।

मुख्य मांगे

1. नई गाइड लाइन के हिसाब से हो मुआवजा का आकलन।
2. कुएं, पेड़, सहित किसान के खेत में आने वाली सभी संपत्ति का अलग से मुआवजा तय हो।
3. जिन किसानों की पूरी जमीन जा रही है उनको जमीन के बदले जमीन भी दी जाए।
4. जिनके मकान जा रहे है उनको पुनर्स्थापित किया जाए।
5 पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए।
6. कई किसानों के खेत में बीच से रोड निकल रहा है, किसान के दोनों ओर बचे खेत में आने-जाने की व्यवस्था की जाए। सड़क की ऊंचाई कम की जाए।
7. मुआवजा प्रकरण तैयार करने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422